वर्ष 12 • अंक 243 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 29 नवंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

खराब प्रबंधन नीति भुगत रहे उपभोक्ता!

संतोष गंगवार ▶▶ पृष्ठ 4

औद्योगिक संबंध विधेयक लोकसभा में पेश

डॉलर रु. 71.60 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 78.80 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37781 ▲ 27 रुपये | सेंसेक्स 41130.20 ▲ 109.60 | निफ्टी 12151.20 ▲ 50.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 12186.00 ▲ 34.90 | ब्रेंट क्रूड 63.50 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

रिलायंस 10 लाख करोड़ रुपये की पहली कंपनी

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसका बाजार पूंजीकरण दस लाख करोड़ रुपये पार कर गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार की समाप्ति पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 10,01,555.42 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का शेयर 0.65 फीसदी बढ़कर 1,579.95 रुपये पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान यह 1,584 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा था। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 0.77 फीसदी चढ़कर ।,582 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी के 2.73 लाख और एनएसई पर 62 लाख शेयर में कारोबार हुआ। पृष्ठ 3

पुरी का वारिस तलाशेगी एचडीएफसी बैंक की समिति

एचडीएफसी बैंक ने अपने मौजूदा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) आदित्य पुरी का उत्तराधिकारी खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक ने इसके लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। पुरी का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। इस बीच, बैंक ने अपने मौजूदा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शशिधर जगदीशन और कंट्री हेड-ऑपरेशंस ऐंड टेक्नोलॉजी-भावेश जवेरी को पदोन्नति देकर कार्यकारी निदेशक बना दिया है और इन्हें निदेशक मंडल में शामिल कर लिया है। पृष्ठ 2

22,800 करोड़ रु. के सैन्य सामान खरीदने की मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 22,800 करोड़ रुपये कीमत के सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मध्य रेंज के पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान पी8आई की खरीद को भी मंजूरी दी। सैन्य साजो-सामान की खरीद का निर्णय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की एक बैठक में किया गया।

वाणिज्यिक प्रतिभूतियों को एनएसई पर कराया सूचीबद्ध

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने गुरुवार को कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदित्य बिड़ला फाइनैंस उसके प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने वाली पहली कंपनी बन गई है। आदित्य बिड़ला फाइनैंस ने अपनी वाणिज्यिक प्रतिभूतियों को 18 नवंबर, 2019 की तिथि से सूचीबद्ध कराया है जिनकी परिपक्वता अवधि 7 फरवरी, 2020 है। सेबी ने अक्टूबर को एक्सचेंजों से कहा था कि वह वाणिज्यिक प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया के लिए जरूरी व्यवस्था करें।

आज का सवाल

क्या एनबीएफसी को उबारने के लिए सीधे हस्तक्षेप करे सरकार

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या कार्वी मामले में होनी चाहिए सख्ती से जांच? हां **66.67%** नहीं **33.33%**

संप्रग मॉडल से उबरेगी एनबीएफसी

एनबीएफसी को नकदी समर्थन, प्रतिभूतियों पर सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव

अर्चिस मोहन, संजीव मुखर्जी और अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 28 नवंबर

उपायों पर विचार

- अगले वित्त वर्ष के आम बजट में हो सकता है इसका प्रावधान
- 2009 में संप्रग सरकार ने भी एनबीएफसी को उबारने के लिए की थी ऐसी ही पहल
- वित्त मंत्रालय इस दिशा में कर रहा है विचार
- एसपीवी के जरिये नकदी मुहैया कराने का प्रस्ताव

नरेंद्र मोदी सरकार संकट में फंसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उबारने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)की पिछली सरकार के मॉडल पर ही काम कर सकती है। सरकार के भीतर एनबीएफसी संकट में सीधे हस्तक्षेप के उस मॉडल की वकालत की जा रही है, जो 2009 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लागू किया था।

सरकार ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को पिछले हफ्ते भेजे एक प्रस्ताव में कहा, 'वित्तीय स्थायित्व के लिए सीधे हस्तक्षेप के उपाय से इस क्षेत्र की चुनौतियां और नकदी संकट दूर करने में मदद मिल सकती है।' वित्त मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय चर्चा की गई है और अगले साल फरवरी में आम बजट में इसे शामिल किया जा सकता है।

वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई वाली संप्रग सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एनबीएफसी क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। इनमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति वाली एनबीएफसी को विशेष उद्देश्य वाली इकाई (एसपीवी) के जरिये नकद सहायता मुहैया कराना शामिल था। जिन एनबीएफसी की गैर-निष्पादित आस्तियां 5 फीसदी से ज्यादा नहीं थीं, उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का पात्र माना गया था। इस योजना से एनबीएफसी की नकदी की स्थिति तेजी से सुधर गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए थे। प्रस्ताव में एनबीएफसी को मौजूदा संकट से उबारने के लिए संप्रग कार्यकाल की योजना को अमल में लाने का पक्ष तो लिया ही गया है, उसका खाका भी तैयार कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि केंद्र इन एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर गारंटी देने के बारे में विचार कर सकता है। गारंटी देने के पीछे जनहित में वित्तीय स्थायित्व को बरकरार रखने का तर्क दिया जा सकता है। ये प्रतिभूतियां सुरक्षित होंगी और इनके एवज में जमानत भी रखी जाएगी। एसपीवी का गठन 2009 की ही तरह सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत किया जा सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार सरकारी गारंटी के आधार पर रिजर्व बैंक एसपीवी द्वारा जारी पीटीसी खरीदेगा। इसके लिए संबंधित एनबीएफसी के पुनर्वित्तपोषण के मकसद से आ रहे वाणिज्यिक पत्रों या कॉर्पोरेट डिबेंचरों को खरीदा जाएगा।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सरकार को आरबीआई अधिनियम की धारा 17 और 18 का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए और आरबीआई द्वारा गैर-सॉवरिन कोलेटरल के एवज में व्यावसायिक क्षेत्र को नकदी मुहैया कराए जाने के लिए ढांचा तैयार करना चाहिए। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए एक विशेष रीपो व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। नोट में कहा गया है, '2009 के आईडीबीआई स्ट्रेस्ड ऐसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड जैसी व्यवस्था कारगर हो सकती है।'

बैंक और गैर-बैंकिंग स्रोतों से व्यावसायिक क्षेत्र को मिलने वाली रकम चालू वित्त वर्ष में कम होकर 1 लाख करोड़ रुपये ही रह गई, जो पिछले वर्ष अप्रैल और सितंबर के बीच करीब 7.36 लाख करोड़ रुपये थी।

प्रस्ताव में कहा गया है, 'ऋण एवं रियल एस्टेट के लिहाज से एनबीएफसी क्षेत्र के सामने आई चुनौतियों का उपभोक्ताओं के हौसले पर और कुल मांग पर असर होता है।' इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार की सक्रिय नीति से इस क्षेत्र की दिक्कतें तेजी से दूर हो सकती हैं।

रोजगार में आरक्षण कर्जमाफी का वादा

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। *पीटीआई*

अनीश फडणीस और अर्चिस मोहन
मुंबई/नई दिल्ली, 28 नवंबर

तीन दलों के गठबंधन महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) की सरकार ने आज शाम मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण कर लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुआई में बनी इस सरकार ने महाराष्ट्र के स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का वादा करने के साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने की भी बात कही है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता जयंत पाटील ने अपनी गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निवासियों को नौकरियों में आरक्षण देने का कानून बहुत जल्द बनाया जाएगा। यह कानून निजी क्षेत्र में सृजित होने वाली नौकरियों पर भी लागू होगा।

- आघाडी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान
- स्थानीय निवासियों को 80 फीसदी रोजगार
- निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की होगी पहल
- किसानों के कर्ज माफ करेगी सरकार

इसके पहले मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भी अपने निवासियों को नौकरियों में आरक्षण देने के प्रावधान लागू किए हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह की आवाजें जोर-शोर से उठी हैं। खास बात यह है कि इस कानून की जद में सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र को भी रखने का जिक्र है। हालांकि इन कानूनों को अभी संबंधित विधानसभाओं से पारित नहीं कराया गया है। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की भागीदारी वाले गठबंधन एमवीए ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले अपनी सरकार का प्रस्तावित एजेंडा पेश किया। तीनों दलों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद सीएमपी को अंतिम रूप दिया जा सका है। इसमें किसानों की कर्ज माफी का भी उल्लेख किया गया है।

शपथ ग्रहण समारोह में तीनों दलों के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शिवाजी पार्क मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे ने शाम छह बजकर 40 मिनट पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा छह मंत्रियों ने भी शपथ ली जिनमें तीनों साझेदार दलों के दो-दो मंत्री शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे एवं सुभाष देसाई, राकांपा से जयंत पाटील एवं छगन भुजबल और कांग्रेस से बालासाहेब थोरात एवं नितिन राउत को मंत्री बनाया गया है। (शेष पृष्ठ 14 पर)

कार्वी-एचएनआई सांठगांठ की जांच करेगा सेबी

समी मोडक
मुंबई, 28 नवंबर

- कार्वी ने ग्राहकों के शेयरों को बैंकों, एनबीएफसी के पास रखा गिरवी
- **600** करोड़ रुपये जुटाने के लिए **2,000** करोड़ रुपये से अधिक के शेयर रखे गिरवी
- कार्वी ने उक्त रकम को पूल खाते में रखने बजाए अपने खाते में हस्तांतरित किया

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और स्टॉक एक्सचेंज कार्वी मामले में इसकी जांच कर रहे हैं कि कहीं इसमें कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके कुछ धनाढ्य निवेशकों की मिलीभगत तो नहीं है। सूत्रों ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) ने अतिरिक्त कमाई के लिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को अपने शेयर गिरवी रखने की सहमति दी हो।

हालांकि शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लेने की औपचारिक व्यवस्था है, खास तौर पर शॉर्ट सेलर ऐसा करते हैं, लेकिन यह ज्यादा चलन में नहीं है। ऐसे में आशंका है कि कुछ निवेशक अपने ब्रोकरों के साथ अनौपचारिक समझौते के तहत ऐसा कर सकते हैं। एक हफ्ते पहले सेबी ने ग्राहकों के शेयरों के दुरुपयोग के मामले में कार्वी की कड़ी आलोचना की थी। कार्वी पर आरोप है कि उसने ग्राहकों के 2,000 करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा के शेयरों को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास गिरवी रखकर 600 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

नियामक से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'जब भी प्रतिभूतियों को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खाते से दूसरे में हस्तांतरित किया जाता है तो सिस्टम के द्वारा अलर्ट भेजा जाता है। संभव है कि कुछ ग्राहकों के संपर्क विवरण अद्यतन नहीं होने की वजह से उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली होगी। हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि भारी-भरकम पोर्टफोलियो वाले निवेशक अपने शेयरों को एक खाते से दूसरे खाते में भेजे जाने के मामले में अनभिज्ञ रहे हों।' सेबी के आदेश के बाद नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कार्वी मामले में ग्राहकों की कितनी राशि और शेयरों का दुरुपयोग किया है, उसकी जांच के लिए ईवाई को नियुक्त किया है। सूत्रों ने कहा कि फॉरेंसिक जांच के नतीजे जल्द ही मिल सकते हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने कथित तौर पर अपनी समूह की फर्म कार्वी रियल्टी में अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2019 के बीच 1,096 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। नियामकीय सूत्रों का कहना है कि सेबी की प्राथमिकता निर्दोष ग्राहकों के अटके पैसे और प्रतिभूतियों को उन्हें सुरक्षित वापस दिलाना सुनिश्चित करना है। सूत्रों ने कहा, 'निवेशकों के हितों की सुरक्षा हमारा मुख्य मकसद है, वहीं यह देखना भी जरूरी है किक कहीं कुछ ग्राहकों ने शुल्क के लिए शेयरों को गिरवी रखने की खातिर ब्रोकरेज के साथ सांठगांठ तो नहीं किया है।'

उद्योग के भागीदारों का कहना है कि ग्राहकों और ब्रोकरेज के बीच सौदा असामान्य नहीं है। ब्रोकिंग के एक अधिकारी ने कहा, 'ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ग्राहक ब्रोकरेज को अपनी ओर से कारोबार करने की पूरी छूट देते हैं। हालांकि जब इसमें नुकसान होता है तो निवेशक हो-हल्ला मचाते हैं।'

पिछले कुछ वर्षों में सेबी और एक्सचेंज ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई नियामकीय बदलाव किए हैं। इनमें ग्राहकों द्वारा दिए गए निर्देश का पूरा विवरण इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या दस्तावेज के तौर पर रखने को कहा गया है। इसके साथ ही जून में जारी परिपत्र में सेबी ने कहा था कि किसी ग्राहक की प्रतिभूतियों को दूसरे ग्राहकों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

100 करोड़ रुपये सालाना कारोबार 1 अप्रैल से ई-इन्वॉयसिंग अनिवार्य

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 28 नवंबर

- स्वैच्छिक स्तर पर 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी यह प्रणाली
- इससे जीएसटी चोरी रोकने और कर अनुपालन आसान बनाने में मिलेगी मदद

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी पर अंकुश लगाने और कर अनुपालन आसान बनाने के वास्ते सरकार 100 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयसिंग अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है। वास्तव में ई-इन्वॉसिंग प्रणाली 1 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक एवं प्रयोगात्मक स्तर पर लागू होगी। शुरू में यह 500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर लागू होगी जबकि 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए 1 फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने गुरुवार को कहा, 'ई-इन्वॉसिंग लागू करने का बुनियादी मकसद करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान बनाना है। इस कदम से जीएसटी रिटर्न प्रणाली और सहज एवं सरल हो जाएगी।' 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले कारोबारों के लिए 7,500 से अधिक जीएसटी पहचान क्रमांक (जीएसटीआईएन) हैं। 1 अप्रैल से ई-इन्वॉयसिंग अनिवार्य होने से 100 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए यह वैकल्पिक हो जाएगा। ई-इन्वॉयसिंग प्रणाली से लघु एवं मझोले उपक्रमों को बैंकों से तत्काल ऋण लेने में मदद मिलेगी। सरकारी की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है,'ई-इन्वॉयसिंग प्रणाली से बैंकों को ढेर सारे दस्तावेज और उनके प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं पेश आएगी। वे ई-इन्वॉयसिंग के आधार पर ऋण चाहने वाली एमएसएमई का मूल्यांकन कर सकेंगे।'

सरकार यह कदम ऐसे समय में उठाने जा रही है जब जीएसटी संग्रह लक्ष्य से कम रही है और सरकार कर चोरी से निपटने के उपाय खोज रही है। सितंबर में जीएसटी संग्रह 91,916 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले 19 महीनों का निम्नतम स्तर था। अक्टूबर में भी संग्रह 95,380 करोड़ रुपये रहा और लगातार तीसरे महीने यह 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा। पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले अक्टूबर में संग्रह 5.3 प्रतिशत कम रहा। डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एम एस मणि ने कहा कि ई-इन्वॉसिंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी पर अंकुश लगाने में आसानी होगी और भविष्य में इससे संग्रह में तेजी आएगी।

खबरों में रहे स्टॉक

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस

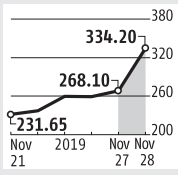

जुलाई 2013 में सूचीबद्ध होने के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी

₹ 268.10 पिछला बंद भाव
₹ 334.20 आज का बंद भाव
▲ 24.65 %

आरबीएल बैंक

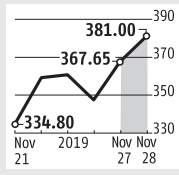

रकम जुटाने पर विचार के लिए 30 नवंबर को होगी निदेशक मंडल की बैठक

₹ 367.65 पिछला बंद भाव
₹ 381.00 आज का बंद भाव
▲ 3.63 %

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज

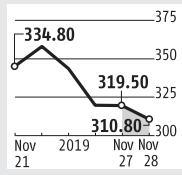

संबंधित पक्षकार के लेनदेन का हवाला देते हुए तीन निदेशकों का इस्तीफा

₹ 319.50 पिछला बंद भाव
₹ 310.80 आज का बंद भाव
▼ 2.72 %

टाटा कम्युनिकेशंस

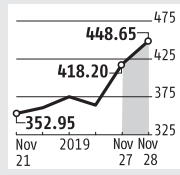

केसिफिक संग वैश्विक आईपी कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा सौदा

₹ 418.20 पिछला बंद भाव
₹ 448.65 आज का बंद भाव
▲ 7.28 %

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

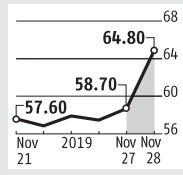

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर

₹ 58.70 पिछला बंद भाव
₹ 64.80 आज का बंद भाव
▲ 10.39 %

संक्षेप में

आईसीआईसीआई सिक्यो. ने सुलझाया मामला

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सेबी के साथ शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन का मामला सुलझा लिया है। निपटान शुल्क के रूप में उसने 28 लाख रुपये का भुगतान किया है। सेबी ने कहा कि आवेदक की अर्जी पर गौर करने के बाद कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया को निपटान किया जा रहा है। यह मामला कुछ इकाइयों द्वारा जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके निष्क्रिय खातों में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और बेचने संबंधी खबरों पर सेबी की जांच से जुड़ा है। *भाषा*

पावर ग्रिड कारोबार अलग करने का प्रस्ताव मंजूर

एबीबी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के बेंगलूरु पीठ ने उसके पावर ग्रिड कारोबार को अलग कर एबीबी पावर प्रॉडक्ट्स ऐंड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (एपीपीएसआईएल) को देने को मंजूरी दे दी है। एबीबी ने नियामकीय सूचना में कहा है, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के बेंगलूरु पीठ ने 27 नवंबर 2019 के अपने आदेश के तहत उसके पावर ग्रिड व्यवसाय को अलग कर एपीपीएसआईएल को देने की योजना को कंपनी कानून 2013 की धारा 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत मंजूरी दे दी। सूचना में कहा गया है कि एनसीएलटी के आदेश की प्रमाणित प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को सौंपे जाने के साथ ही योजना प्रभावी हो जाएगी। *भाषा*

पुरी के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

एचडीएफसी बैंक ने बनाई छह सदस्यीय खोज समिति, बोर्ड ने शशिधर जगदीशन, भावेश जवेरी को पदोन्नत कर कार्यकारी निदेशक बनाया, पुरी अक्टूबर 2020 में होंगे सेवानिवृत्त

निधि राय
मुंबई, 28 नवंबर

एचडीएफसी बैंक ने मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी की तलाश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बैंक ने छह सदस्यीय समिति नियुक्त की है। पुरी का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रहा है।

इस बीच, बैंक ने मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी शशिधर जगदीशन और कंट्री हेड (परिचालन व तकनीक) भावेश जवेरी को कार्यकारी निदेशक बना दिया है और बोर्ड में भी शामिल किया है। जगदीशन बैंक के साथ 1996 से जुड़े हुए हैं। जवेरी साल 1998 में बैंक के साथ जुड़े। इनकी नियुक्ति आरबीआई और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगी। एक्सचेंज को भेजी सूचना में बैंक ने कहा, खोज समिति में श्यामला गोपीनाथ, संजीव सच्चर, एमडी रंगनाथ, संदीप पारिख, श्रीकांत नाधामुनि, केकी मिस्त्री शामिल होंगे। मिस्त्री एचडीएफसी हाउसिंग फाइनैंस के प्रतिनिधि होंगे।

पुरी इस खोज समिति के सलाहकार के तौर पर भी काम करेंगे। अगले कुछ महीने में समिति आंतरिक व बाहरी उम्मीदवारों का आकलन करेगी ताकि आगे काम आसान हो।

इस बात के कयास लगाए जाते रहे हैं कि बैंक का अगला एमडी कौन होगा और डिप्टी एमडी परेश सुख्तांकर को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन अगस्त 2018 में उनकी अचानक निकासी से इस कयास पर विराम लग गया।

पुरी और एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारिख ने अनपी टिप्पणी में कहा है कि उत्तराधिकारी बाहर का हो सकता है और जरूरी नहीं कि बैंक के भीतर का ही कोई व्यक्ति हो। निजी क्षेत्र के कई बैंकों ने भी नेतृत्व में बदलाव देखा है। ऐक्सिस बैंक की प्रबंध निदेशक व सीईओ शिखा शर्मा करीब नौ साल तक प्रमुख बने रहने के बाद दिसंबर 2018 में पद छोड़ दिया। आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोछड़ की जगह संदीप बख्शी मार्च में मुख्य परिचालन अधिकारी बने। येस बैंक ने भी बदलाव देखा जब मार्च 2019 में राणा कपूर की जगह नवनीत गिल प्रबंध निदेशक और सीईओ बने। गिल डॉयचे बैंक से आए हैं।

इंडसइंड बैंक भी मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी रमेश सोबती के उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो रहा है जब वे 70 साल के हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक ने संभावित उत्तराधिकारी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।

कौन बनेगा एचडीएफसी बैंक का प्रमुख

- खोज समिति में श्यामला गोपीनाथ, संजीव सच्चर, एमडी रंगनाथ, संदीप पारिख, श्रीकांत नादमुनि, केकी मिस्त्री शामिल होंगे
- मिस्त्री एचडीएफसी हाउसिंग फाइनैंस के प्रतिनिधि होंगे। पुरी इस खोज समिति के सलाहकार के तौर पर भी काम करेंगे
- डिप्टी एमडी परेश सुकथनकर को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। लेकिन अगस्त 2018 में उनकी अचानक निकासी से इस कयास पर विराम लग गया

छंटनी पर टाटा स्टील व श्रम संगठनों में ठनी

रॉयटर्स
लंदन, 28 नवंबर

टाटा स्टील यूरोप ने बुधवार को कहा कि उसने एक 'सुधार कार्यक्रम' को लेकर अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू की थी, जिसमें 3,000 लोगों की छंटनी भी शामिल है। कंपनी के इस बयान कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए श्रम संगठन के नेताओं ने कहा कि योजना में संशोधन की जरूरत है।

कंपनी ने मुनाफे में सुधार के लिए 18 नवंबर को पुनर्गठन योजना की घोषणा की थी। कंपनी ने बुधवार को कहा कि नीदरलैंड में 1,600, ब्रिटेन में 1,000 और अन्य जगहों पर 350 लोगों की छंटनी किए जाने की योजना बनाई गई थी। इसने कहा कि दो-तिहाई छंटनी प्रबंधन और कार्यालयी कर्मचारियों की होने के आसार हैं। प्रतिस्पर्धा नियामकों ने जून में जर्मनी की टिसेनक्रुप के साथ संयुक्त उद्यम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पुनर्गठन का यह कदम उठाया गया है।

ब्रिटेन और नीदरलैंड्स की यूनियनों ने कहा कि वह समझौता नहीं हो पाने के बाद उन्हें वर्ष 2021 तक नौकरी की गारंटी दी गई थी और उन्हें उम्मीद है कि कंपनी अपने वादे पर अडिग रहेगी। ब्रिटिश स्टीलवर्कर्स यूनियन के महासचिव रॉय रिकहुस ने कहा कि टाटा की अपनी यूरोपियन वर्क्स काउंसिल के साथ बातचीत में शामिल होने वाले यूनियन प्रतिनिधियों ने कंपनी को बताया था कि उनकी योजना 'सोच-समझकर नहीं बनाई गई है और इसमें संशोधन की दरकार है।'

टाटा ने कहा है कि उनके प्रस्ताव लंबी अवधि के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यूनियनों ने कहा कि निवेश योजना को शामिल करने वाले विजन का लगातार अभाव बना हुआ है। रिकहुस ने ईमेल के जरिये एक बयान में कहा, 'ऐसा लगता है कि कंपनी केवल गिरावट को रोक रही है और हमें दिशा में एक अहम बदलाव की जरूरत है, जो कामगारों को इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि उनका भविष्य है।' इस मुद्दे पर आगामी सप्ताह में चर्चा होनी है। पूरे यूरोप में इस्पात क्षेत्र अतिरिक्त क्षमता और ऊंची लागत की समस्या से जूझ रहा है।

रद्द नहीं हो एयरसेल का लाइसेंस

सुब्रत पांडा
मुंबई, 28 नवंबर

कर्ज चुकाने में असमर्थ दूरसंचार कंपनी एयरसेल को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है कि कंपनी का दूरसंचार लाइसेंस रद्द नहीं किया जाए क्योंकि 'लाइसेंस के बिना कोई भी समाधान आवेदक कंपनी को उबारने में रुचि नहीं दिखाएगा।' एम के श्रावत और चंद्रभान सिंह की अध्यक्षता वाले पीठ ने अपने आदेश कहा, 'लाइसेंस रद्द होने से कंपनी के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। यह कंपनी केवल लाइसेंस के आधार पर ही देश में दूरसंचार कारोबार चला रही है। इसलिए ऋणी कंपनी के कारोबार के लिए लाइसेंस अत्यंत जरूरी है।'

न्यायाधिकरण ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार किया कि लाइसेंस या स्पेक्ट्रम देश की परिसंपत्ति है, जिस पर ऋणी कंपनी (एयरसेल) को स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि समाधान पेशेवर (आरपी) ने लाइसेंस के 'स्वामित्व' की मांग नहीं की है। उसने केवल तब तक इसके अबाधित उपयोग की मांग की है, जिसे लेकर सहमति बन चुकी है। न्यायाधिकरण ने कहा कि ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 14 की उपधारा (2) में कहा गया है कि ऋणी कंपनी को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति तय अवधि तक बंद, स्थगित या बाधित नहीं की जानी चाहिए। ऋणी कंपनी दूरसंचार लाइसेंस का इस्तेमाल कारोबारी उद्देश्य के लिए करती है, इसलिए तय अवधि का प्रावधान लागू होगा।

एस्सार के ऋणदाताओं को मिलेगी समाधान से ज्यादा राशि

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 28 नवंबर

एस्सार स्टील के ऋणदाताओं को कंपनी की समाधान प्रक्रिया से 42,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम मिल सकती है। सूत्रों ने कहा कि ऋणदाताओं और आर्सेलरमित्तल ने आपसी सहमति से एस्सार के एबिटा के ऑडिट के लिए ग्रांट थॉर्टन को नियुक्त करने को तैयार हो गए हैं। यह एबिटा ऋणदाताओं को मिलेगा।

ग्रांट थॉर्टन ने ग्राहक गोपनीयता प्रावधान का हवाला देते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आर्सेलरमित्तल ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरएफपी) दस्तावेज के प्रावधानों के मुताबिक एबिटा ऋणदाताओं को मिलेगा। न्यूनतम गारंटी 2,500 करोड़ रुपये है। बोली के मुताबिक आर्सेलरमित्तल 39,500 करोड रुपये का अग्रिम भुगतान कर रही है और 2,500 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी पर सृजित लाभ से समायोजित किए जा रहे हैं। इस तरह कुल राशि 42,000 करोड़ रुपये होती है।

एस्सार के एक बड़े ऋणदाता ने कहा, '2,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि भी ऋणदाताओं को मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'इस तरह ऋणदाताओं को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम मिलेगी। हमारा मानना है कि एबिटा 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये हो सकता है।' हालांकि ग्रांट थॉर्टन के ऑडिट पूरा करने के बाद वास्तविक राशि का पता चल पाएगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में सुनवाई के दौरान एस्सार के समाधान पेशेवर ने कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान सृजित लाभ का एक हलफनामे में खुलासा किया था। लाभ का यह आंकड़ा कार्यकारी सीएफओ और एल्वारेज ऐंड मार्शल द्वारा मुहैया कराए गए ब्योरों पर आधारित था। इसके मुताबिक मार्च 2019 तक अस्थायी आंकड़ा 4,229 करोड़ रुपये था।

रिलायंस बनी 10 लाख करोड़ रुपये की कंपनी

मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन गुरुवार को 10 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया और इस तरह से यह कंपनी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई और वैश्विक स्तर पर 64वीं सबसे मूल्यवान कंपनी। पिछले दो वर्षों से आरआईएल का शेयर तेजी से चढ़ रहा है, जिसकी वजह दूरसंचार और खुदरा कारोबार की मजबूत रफ्तार है। आरआईएल भारत की न सिर्फ सबसे मूल्यवान कंपनी है बल्कि भारतीय कंपनी जगत में उसकी शुद्ध बिक्री व लाभ सबसे ज्यादा है। भारत के कुल बाजार पूंजीकरण में अकेले रिलायंस की हिस्सेदारी 6.5 फीसदी है। साथ ही आरआईएल और दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस के बाजार पूंजीकरण का अंतर अब करीब 30 फीसदी पर पहुंच गया है। डॉलर के लिहाज से आरआईएल का मूल्यांकन 140 अरब डॉलर है, जो वैश्विक तेल व गैस दिग्गज फ्रांस की टोटाल और चीन की पेट्रोचाइना से थोड़ा नीचे है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि खुदरा, डिजिटल कारोबार और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के चलते आरआईएल का बाजार पूंजीकरण 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। *समी मोडक*

बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 10 अग्रणी भारतीय कंपनी

भारतीय रैंकिंग	वैश्विक रैंकिंग	कंपनी	बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपये)
1	64	रिलायंस इंडस्ट्रीज	10,01,555
2	100	टीसीएस	7,79,505
3	111	एचडीएफसी बैंक	6,92,615
4	196	एचयूएल	4,51,480
5	224	एचडीएफसी	3,98,992
6	299	आईसीआईसीआई बैंक	3,35,686
7	322	एसबीआई	3,11,424
8	324	कोटक महिंद्रा बैंक	3,08,612
9	334	आईटीसी	3,03,054
10	351	इन्फोसिस	2,98,795

स्रोत : ब्लूमबर्ग/एक्सचेंज संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

इंडियाबुल्स को मिली फौरी राहत

कंपनी मंत्रालय ने अभी तक इंडियाबुल्स के खिलाफ जांच बंद नहीं की है

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 28 नवंबर

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस की तरफ से पांच कंपनियों को आवंटित ऋणों में अब तक कोई अनियमितता नहीं पाई है। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक इंडियाबुल्स के खिलाफ जांच बंद नहीं की है और दो महीनों के भीतर नया हलफनामा जमा करने की इजाजत मांगी है।

मंत्रालय ने कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर इंडियाबुल्स के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आज दायर एक हलफनामे में आवंटित ऋणों की जांच के बारे में यह जानकारी दी। न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में इंडियाबुल्स को दिए गए कर्जों पर सवाल खड़े किए गए थे। गैर-सरकारी संगठन 'सिटिजंस व्हिसल ब्लोअर फोरम' ने यह याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ के समक्ष यह हलफनामा दायर किया गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।

रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देने वाली कंपनी इंडियाबुल्स को बांटे गए कर्जों की जांच अभी जारी रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अभी कोई क्लीनचिट नहीं दी गई है और निरीक्षण रिपोर्ट की पुष्टि के बाद हम एक और हलफनामा दायर करेंगे।'

बहरहाल इस सकारात्मक हलफनामे की खबर आते ही शेयर बाजार में इंडियाबुल्स के शेयरों के भाव 347.65 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ फिर भी इसके शेयर 24.7 फीसदी के उछाल के साथ 334.20 के भाव पर बंद हुए।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के प्रबंध निदेशक गगन बंगा ने कहा कि यह हलफनामे उनके दावे की ही पुष्टि कर रहा है। बंगा ने कहा, 'जनहित याचिका में जिन पांच कर्जों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनके बारे में कंपनी मंत्रालय की तरफ से दायर हलफनामा उसी बात की पुष्टि करता है जिसे हम छह महीनों से कह रहे थे। हम मंत्रालय एवं नियामकीय संस्थाओं के साथ पूरी तरह पारदर्शी रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि तथ्यों के दम पर हमारी जीत होगी।'

कंपनी मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि इंडियाबुल्स से कर्ज लेने वाली पांच कंपनियों में से डीएलएफ, रिलायंस एडीएजी और एम्प्रीकॉर्प ने समूची राशि का पुनर्भुगतान कर दिया है जबकि वाटिका एवं चोर्डिया समूह नियमित तौर पर कर्ज की किस्तें भर रहे हैं। गत 27 सितंबर को अदालत में दाखिल एक जनहित याचिका में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस पर पैसे इधर-उधर करने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा था कि मामला अदालत में लंबित रहने से उसे नुकसान हो रहा है।

कंपनी मामलों के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) का कार्यालय इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम इस मामले से जुड़े दो ट्रक कागजात की जांच कर चुके हैं। लेकिन हमारी जांच अब भी जारी है।'

अब तक नहीं पाई गई अनियमितता

■ इस खबर के बाद एक्सचेंज में इंडियाबुल्स के शेयरों के भाव 347.65 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ, फिर भी इसके शेयर 24.7 फीसदी के उछाल के साथ 334.20 के भाव पर बंद हुए

ओएनजीसी ने बॉन्ड से जुटाए 30 करोड़ डॉलर

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 28 नवंबर

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी ने पूंजीगत खर्च पूरा करने के लिए डॉलर बॉन्ड के जरिए 30 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इस बॉन्ड पर ब्याज दर 3.375 फीसदी है और यह 2029 में परिपक्व होगा। किसी भारतीय कंपनी की तरफ से 10 वर्षीय या इससे ज्यादा अवधि वाले बॉन्ड पर सबसे कम ब्याज है। कंपनी ने आज एक बयान में कहा कि बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों में सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, लंदन, ताइवान, जापान और पश्चिम एशिया के निवेशक शामिल हैं, जिनमें एशियाई से 77 फीसदी बोली, यूरोप और अफ्रीकी निवेशकों की 23 फीसदी बोली शामिल है। इस बॉन्ड कार्यक्रम से जुड़े बैंकर थे सिटी, डीबीएस बैंक, एमयूएफजी, एसबीआईकैप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ओएनजीसी ने 32,921 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का खाका खींचा है। ओएनजीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शशि शंकर ने कहा कि ओएनजीसी अपने परिचालन का वित्त पोषण आंतरिक स्रोतों से करती है और उसके पास भविष्य में भी ऐसा करने की क्षमता है। डॉलर बॉन्ड की पेशकश हालांकि ओएनजीसी समूह के लिए बेंचमार्क तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो एचपीसीएल के अधिग्रहण के बाद एकीकृत ऊर्जा दिग्गज बन गई है। अनुमान लगाया जाता है कि जब बेंचमार्क तय हो जाता है तो यह समूह की इकाइयों को प्रतिस्पर्धी दर पर रकम जुटाने में मदद करता है।

2020 में ज्यादातर देसी कंपनियों की साख होगी कमजोर : मूडीज

अभिजित लेले
मुंबई, 28 नवंबर

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि आर्थिक रफ्तार में सुस्ती और लाभ के मोर्चे पर नरमी से साल 2020 में ज्यादातर गैर-वित्तीय भारतीय कंपनियों की साख की स्थिति कमजोर होगी।

कर्ज के उच्चस्तर, कमजोर लाभ और आर्थिक मंदी जारी रहने के कारण रेटिंग वाली फर्मों का क्रेडिट प्रोफाइल 2020-21 में शायद ही बहुत ज्यादा सुधरेगा। मूडीज के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी कौस्तुभ चौबाल ने कहा, यह निवेश व उपभोग दोनों पर दबाव डाल रहा है।

नवंबर में मूडीज की तरफ से भारत की सॉवरिन रेटिंग का परिदृश्य नकारात्मक किए जाने के बाद उसकी रेटिंग वाली 45 कंपनियों का 51 फीसदी का परिदृश्य नकारात्मक है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की स्थिति स्थिर बनी रहेगी, जिसे बाजार के मजबूत पोजीशन का सहारा मिलेगा।

मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार 2020 में घटकर 6.6 फीसदी रहेगी, जो पिछले वर्षों का कमजोर आंकड़ा होगा और निकट भविष्य में क्रेडिट की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी राहत पैकेज की संभावना सीमित रहेगी।

फंडिंग की स्थिति भी सख्त बनी हुई है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग धीमी है और कंपनियों को कर्ज देने के मामले में बैंकों के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार आ रही गिरावट ने रेटिंग वाली कंपनियों के क्रेडिट पर असर सीमित कर दिया है क्योंकि ज्यादातर ने हेजिंग की है।

निवेशकों की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

शेयर बाजारों में दो दिन की तेजी से निवेशकों की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए। कारोबार समाप्त होने के बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,87,370.56 करोड़ रुपये बढ़कर 1,55,57,484.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। *भाषा*

बेरिंग्स पीई निदेशक ने छोड़ दिया था कार्वी बोर्ड

देव चटर्जी
मुंबई, 28 नवंबर

बाजार नियामक सेबी और बेंगलूरु पुलिस की तरफ से इस साल जून में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड की जांच शुरू होने के तुरंत बाद प्राइवेट इक्विटी फर्म बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया के इकलौते प्रतिनिधि आशिष अग्रवाल ने जुलाई में केएसबीएल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। बेरिंग्स एशिया ने साल 2007 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में निवेश किया था और कंपनी की 20 फीसदी हिस्सेदारी ली थी, साथ ही उसे केएसबीएल के निदेशक मंडल में भी जगह मिली थी।

बेरिंग्स एशिया के प्रवक्ता ने कहा, बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया कार्वी से अपना निवेश निकाल रही है और अग्रवाल का इस्तीफा इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। न तो बेरिंग और न ही अग्रवाल को इस्तीफे के समय सेबी की तरफ से हो रही जांच की जानकारी थी।

बेरिंगग्स ने नवंबर 2007 में आईसीआईसीआई वेंचर्स के साथ हिस्सेदारी ली थी और दोनों के पास केएसबीएल की 30.95 फीसदी हिस्सेदारी थी। दोनों प्राइवेट इक्विटी फर्मों ने पैसिफिक सेंचुरी समूह की पूरी 20 फीसदी हिस्सेदारी और अतिरिक्त 10 फीसदी हिस्सेदारी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में निवेश के जरिए ली थी। वित्त वर्ष 2017 में कार्वी समूह के प्रवर्तक ने आईसीआईसीआई वेंचर की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया जबकि कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होनी शुरू हो गई थी।

इस साल जून में बेंगलूरु की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कई निवेशकों ने स्थानीय पुलिस से कार्वी वेल्थ की तरफ से भुगतान में चूक की शिकायत की। पुलिस ने अग्रवाल व सहायक कंपनी कार्वी रियल्टी व कार्वी कैपिटल के समेत सभी निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत करने वालों ने पुलिस से कहा था कि कंपनी ने कुछ और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और उन्हें साल 2017 से कोई रिटर्न नहीं मिला है। निवेशकों को पेश की गई प्रतिभूति पर 18 से 20 फीसदी रिटर्न की बात कही गई थी। एक बयान में कार्वी ने निवेशकों के आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि इन निवेशकों ने उच्च प्रतिफल-उच्च जोखिम वाली प्रतिभूतियों में निवेश किया था और उसने ग्राहकों को न तो गलत जानकारी दी और न ही उसके साथ धोखाधड़ी की।

बीएस बातचीत

देसी जरूरत के मुताबिक समाधान मुहैया कराने पर विचार

सिंधु गंगाधरन जर्मनी में करीब 18 साल बिताने के बाद हाल में सैप लैब्स इंडिया की प्रबंध निदेशक बनकर भारत लौटी हैं। सैप लैब्स इंडिया की पहली महिला प्रमुख बनने वाली गंगाधरन ने **समरीन अहमद** के साथ साक्षात्कार में सैप लैब्स इंडिया को लेकर अपनी तात्कालिक प्राथमिकताओं और कंपनी की वृद्धि की योजनाओं के बारे में बातचीत की। बातचीत के अंश :

सैप लैब्स इंडिया को लेकर आपकी तात्कालिक प्राथमिकताएं क्या हैं?

मैंने सैप लैब्स के लिए एक विजन तैयार किया है, जिसके चार स्तंभ हैं। पहला नवोन्मेष और ग्राहक केंद्रित बनने पर ध्यान देना है। दूसरा स्तंभ वैचारिक नेतृत्व है। तीसरा समग्र उत्पाद मुहैया कराने पर जोर देना है। क्लाउड तकनीक में हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इसलिए समग्र उत्पाद मुहैया कराने पर ध्यान देना अहम हो जाता है। चौथा समावेश की संस्कृति बनाना है।

वैश्विक स्तर पर कंपनी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में भारत में कितने मौके हैं?

भारत में बहुत से अवसर हैं। देश में हमारे पास बड़ी तादाद में प्रतिभाएं हैं। हमारे कर्मचारियों की औसत उम्र 32 वर्ष है। इसका मतलब है कि वे नए विचारों और तकनीकों पर काम करने के लिए तैयार हैं, भले ही यह एआई, एमएल या ब्लॉकचेन हो।

भविष्य की तकनीक के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जिन पर सैप लैब्स (इंडिया) काम कर रही है?

हम विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे भारत और चीन के बाजारों को उनकी जरूरत के मुताबिक समाधान मुहैया कराए जाएं। ये कीमत संवेदनशील बाजार हैं और हम सभी के लिए एकसमान उत्पादों में भरोसा नहीं रखते हैं। हम छोटी और मझोली कंपनियों की कार्यप्रणाली के ऑटोमेशन के बारे में विचार कर रहे हैं।

वर्ष 2020 तक नियुक्तियों को लेकर आपका क्या आउटलुक है?

हम नए और अनुभवी लोगों की नियुक्ति में संतुलन रखते हैं। हम हर साल करीब 800 लोगों की भर्ती के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारे पास विशेषज्ञता वाले लोग हैं, लेकिन हम नए विचारों वाले लोगों को लाना चाहते हैं।

सैप ने क्लाउड पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में उसका वैश्विक राजस्व वर्ष 2023 तक तीन गुना बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाएगा। यह लक्ष्य हकीकत के कितना नजदीक है?

हम ग्राहकों को समझदार उद्यम बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन्हें एक फ्रेमवर्क मुहैया करा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर चीजें क्लाउड पर केंद्रित हैं। अब बहुत सी उभरती तकनीकों को हमारे मुख्य क्लाउड उत्पादों में शामिल किया जा रहा है। पिछले एक दशक के दौरान हमने एचआर, बिज़नेस नेटवर्क, यात्रा एवं खर्च प्रबंधन, विनिर्माण और आपूर्ति शृंखला में कई अधिग्रहण किए हैं।

कंपनी के लिए भारत कितना अहम बाजार है?

हमारी पिछले 20 साल से भारत में मजबूत मौजूदगी इसे बयां करती है। भारत में हमारे 13,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से 8,500 अनुसंधान एवं विकास टीम में हैं। हम बेंगलूरू में अपने कार्यालय का विस्तार करेंगे। हम इस शहर में दूसरा परिसर स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

आपके लिए भारत से जर्मनी जाना और अब वापस भारत लौटना कैसा रहा है?

जब मैं 2001 में जर्मनी गई थी, तब सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी। जब जर्मन बोलने लगी तो यह चुनौती खत्म हो गई। जर्मनी में 18 साल रहकर और फिर अपने गृह शहर बेंगलूरु में वापस आने पर मुझे यहां यातायात चुनौतीपूर्ण लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि तकनीक का इस्तेमाल करके सरकार और हम इसका समाधान खोज सकते हैं।

औद्योगिक संबंध विधेयक लोकसभा में पेश

सोमेश झा
नई दिल्ली, 28 नवंबर

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में राज्यों को छंटनी नियम आसान करने को लेकर राज्य सरकारों को विशेष अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है।

सरकार अपने 2015 के प्रस्ताव से वापस हट गई है, जिसमें फैक्टरियो में 300 तक कर्मचारी रहने पर उन्हें सरकार की अनुमति के बगैर कर्मचारियों की छंटनी, उन्हें हटाने या फैक्टरी बंद करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। इस समय 100 कर्मचारियों तक वाली फैक्टरियां ऐसा कर सकती हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'मौजूदा प्रावधानों में लचीचापन लाने के लिए (छंटनी आदि से संबंधी) उचित सरकार से पूर्व अनुमति लेने की सीमा में कोई बदलाव न करते हुए 100 कर्मचारी रखा गया है। लेकिन इस तरह के कर्मचारियों की संख्या, अधिसूचना के माध्यम से बदलने का प्रावधान जोड़ा गया है।'

ऐसा करके विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकारों को नियोक्ता को कर्मचारियों की संख्या कम या ज्यादा करने के मामले में अधिकार देने के लिए संसद या विधानसभा में न जाना पड़े। यह प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का हिस्सा था, जो मौजूदा कानून के विवादास्पदज प्रावधानों में से एक है।

नियोक्ता यह मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या की सीमा बढ़ाकर बड़ी कंपनियों (कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से) छटनी या प्रतिष्ठान बंद करने का अधिकार मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत न हो। वहीं मजदूर संगठन इस तरह के किसी कदम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मजदूर संगठन कर्मचारियों की संख्या की सीमा और कम किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि छोटी फर्मों को भी अपनी इकाई से कर्मचारियों को निकालने या संयंत्र बंद करने के पहले सरकार को सूचित करना पड़े।

सरकार ने छंटनी प्रभावित कर्मचारियों के लिए पुन:कौशल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस कोष में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के अंतिम वेतन निकासी के 15 दिन के बराबर का वेतन होगा, जो कर्मचारी की छंटनी या फैक्टरी बंद होने के पहले के हिसाब से होगा।

विधेयक के मुताबिक कर्मचारी द्वारा अंतिम महीने लिए गए वेतन के 15 दिन की राशि से तैयार किए गए इस कोष का इस्तेमाल इस तरह की छंटनी के 45 दिन के भीतर तय किए गए मानकों के मुताबिक होगा।

औद्योगिक संबंध संहिता में ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926, इंडस्ट्रियल इंप्लाइमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर) ऐक्ट, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्योगों को सीधे ठेके के कर्मचारियों की भर्ती में मदद करने के लिए सरकार ने श्रम कानून में नियत अवधि के रोजगार की अवधारणा का प्रस्ताव किया है। इस विधेयक में नियत अवधि के रोजगार के लिए कानूनी ढांचे का प्रस्ताव किया गया है, जिसके माध्यम से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी उस इकाई में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेगा।

लंबे समय से बदलाव की कवायद

- श्रम एवं रोजगार मंत्री ने लोकसभा में पेश किया औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019
- सरकार 2015 के प्रस्ताव से हटी, जिसमें 300 तक कर्मचारी रहने पर बगैर सरकार की अनुमति छंटनी या संयंत्र बंद करने का अधिकार देने का प्रस्ताव था
- अब पहले की तरह ही 100 कर्मचारी रहने पर छंटनी का प्रावधान बना रहेगा
- नियोक्ता यह संख्या बढ़ाने, जबकि मजदूर संगठन इसे और कम करने की मांग कर रहे हैं
- सरकार ने प्रावधान किया है कि श्रमिकों की यह संख्या अध्यादेश के माध्यम से तय की जा सकेगी, केंद्र व राज्यों को इसके लिए क्रमशः लोकसभा व विधानसभा नहीं जाना होगा
- छंटनी प्रभावित कर्मियों के लिए पुनः कौशल फंड का प्रस्ताव

अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी

सरकार ने वर्ष 2019-20 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के तहत 21,246.16 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जिसमें 8,820 करोड़ रुपये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मद में मांगे गए हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 64 अनुदान मांगों तथा दो विनियोग का प्रस्ताव रखा।

इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019..20 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के तहत 21,246.16 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जाता है। इसमें से निवल नकद व्यय 18995.51 करोड़ रुपये का है। सकल अतिरिक्त व्यय में 2249 करोड़ रुपये का प्रबंध मंत्रालयों, विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों से किया जाएगा। अनुदान की मांगों के दस्तावेज के अनुसार, 14वें वित्त आयोग पंचाट के स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान की मांगों के लिए 8820.62 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी गई है जिसमें राजस्व घाटा अनुदान के हिस्से के मद में 5892 करोड़ रुपये, स्थानीय निकाय अनुदान मद में 725 करोड़ रुपये और एसडीआरएफ मद में 139 करोड़ रुपये शामिल हैं। नवंबर एवं दिसंबर 2019 के लिए करों से हुई निवल आय का राज्य का हिस्सा 2063.62 करोड़ रुपये है।

सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में पुनर्पूंजीकरण बांड को जारी करके पूंजी निवेश के लिए अपने हिस्से के तौर 2500 करोड़ रुपये के अनुदान की मांगों की मंजूरी मांगी। *भाषा*

ओला, उबर का तय हो सकता है कमीशन

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 28 नवंबर

- इससे ओला उबर के चालकों को मिल सकता है तात्कालिक लाभ, ऐप से टैक्सी चलाने वाले खुश
- उद्योग में डर है कि इससे प्राकृतिक बाजार की गतिविधि में हस्तक्षेप होगा और यह बेहतरी के बजाय बुरा साबित हो सकता है

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही ओला और उबर जैसे ऐप आधारित टैक्सी ऑपरेटरों के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी करेगी, जिसमें अन्य चीजों के साथ चालकों से कंपनियों द्वारा लिए जा रहे कमीशन की सीमा तय करने का प्रस्ताव है। इस कदम का जहां चालक स्वागत कर रहे हैं, वहीं उद्योग इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। उद्योग जगत का डर है कि बाजार की प्राकृतिक चाल में हस्तक्षेप बेहतरी से ज्यादा बुरा साबित हो सकता है।

यह शुल्क बदलता रहता है, लेकिन यह ट्रिप के किराये के 20 प्रतिशत के आसपास होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसे 10 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो इसका सीधा असर कैब एग्रीगेटरों की कमाई पर पड़ेगा, जो पहले से ही कीमतों के प्रति संवेदनशील बाजार के चलते घाटे में चल रहे हैं। ओला और उबर का इस बाजार पर कब्जा है। यह दोनों कंपनियां लगातार किराया सस्ता करने और चालकों को प्रोत्साहन देने का होड़ करती हैं। दिल्ली स्थित परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसका पूरा ब्योरा देने से इनकार किया, लेकिन कहा कि मसौदा नीति जल्द जारी की जाएगी। इसे लोगों के विमर्श के लिए रखा जाएगा।

ओरियस वेंचर पार्टनर्स के सह संस्थापक और वेंचर कैपिटलिस्ट रेहान यार खान ने कहा, 'कीमतों का नियमन किसी भी रूप में किया जाए, वह बमुश्किल प्रभावी होता है।' उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'इसके बजाय जिस तरह से दूरसंचार, एयलाइंस, खुदरा आदि क्षेत्र काम करते हैं, उससे प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसके बाद अगर कोई कारोबारी ज्यादा मुनाफा लेता है तो अन्य कारोबारी दाम घटाने में लग जाते हैं और बाजार सामान्य हो जाता है।'

सरकार शीघ्र जारी करेगी भारत बॉन्ड ईटीएफ

अनूप रॉय
मुंबई, 28 नंवबर

सरकार समर्थित ऋण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को तीन और 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल के सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इसे दिसंबर या जनवरी के आरंभ में लाया जा सकता है।

मंत्रिमंडलीय मंजूरी के लिए इसे बुधवार को पेश किया जाना था लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि 4 दिसंबर तक इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है जिसके बाद शीघ्र ही इसे जारी किया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने ऋण ईटीएफ के पहले अंश को जारी करने के लिए एडलवाइस संपत्ति प्रबंधन को नियुक्त किया है। इस ईटीएफ को भारत बॉन्ड ईटीएफ के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि इस इटीएफ के और भी अंश हो सकते हैं जिनको जारी करने के लिए दूसरे संपत्ति प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकती है।

सूत्रों ने कहा कि ऋण ईटीएफ के लिए एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड सरकार की एकमात्र सलाहकार है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी ऋण ईटीएफ पात्र इकाइयों को रीपो के लिए अनुमति दी है जिसका मतलब है कि ये इकाइयां रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखकर वहां से एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं।

ईटीएफ का मकसद बॉन्ड बाजार में खुदरा भागीदारी को बढ़ाना है। साथ ही इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए फंड के दूसरे स्रोत तैयार करना है। बॉन्ड ईटीएफ निवेशकों को किफायती तरीके से बॉन्ड जैसे निवेशों को खड़ा करने और उसे बनाए रखने के लिए एक जरिया प्रदान करेगा।.

ईटीएफ को म्युचुअल फंड की तर्ज पर खरीदा और भूनाया जा सकता है। इसका प्रारूप एक खुले फिक्स्ड मैच्युरिटी की तरह होगा और इसके लिए अप्रैल 2023 और अप्रैल 2030 दो परिपक्वता अवधि होगी। रेखांकित बॉन्ड से मिलने वाले कूपन को फिर से निवेश किया जा सकेगा। 5 फीसदी तक सरकारी प्रतिभूतियों या जमानती उधारी और ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) को तरलता प्रबंधन के लिए आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा एक फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) शुरू किया जाएगा जो अपनी पूरी रकम भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करेगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने ईटीएफ के लिए एएए से लेकर एए रेटिंग वाली सरकारी कंपनियों की पहचान की है लेकिन पहले एएए रेटिंग वाली कंपनियों को ही इसके लिए चुना जाएगा।

इन कंपनियों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), एनएचपीसी, पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रेलवे वित्त निगम, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, कोंकण रेलवे, भारतीय निर्यात आयात बैंक, टीएचडीसी इंडिया, आवास और शहरी विकास निगम और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर शामिल हो सकती हैं।

हालांकि कोई जारीकर्ता यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं रह जाए या फिर उसमें सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे चली जाए तो उसे इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए, बीपीसीएल के निजीकरण के बाद वह इसके लिए योग्य नहीं रह जाएगी। ऐसा ही टीएसडीसी और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर के साथ भी होगा।

भारत बॉन्ड ईटीएफ का एक निश्चित परिपक्वता दिनांक होगा और यह सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों द्वारा जारी किए गए उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड में निवेश करेगा। ये बॉन्ड ईटीएफ के परिपक्वता दिनांक या उससे पहले परिपक्व हो जाएंगे।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

- 3 साल और 10 साल होगी बॉन्ड परिपक्वता की अवधि
- 4 दिसंबर को मिल सकती है प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- इस योजना के लिए एके कैपिटल सरकार की एकमात्र सलाहकार

जीएसटी की समस्याएं हल न होने पर अदालत सख्त

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 28 नवंबर

दिल्ली उच्च न्यायालय जीएसटी संबंधी शिकायतों का निवारण न होने पर सख्त हो गया है। उच्च न्यायालय बीते कुछ महीनों से बिक्री कर बार एसोसिएशन दिल्ली व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर कई निर्देश दे चुका हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत के आदेश पर भी उनकी शिकायतों का ढंग से निवारण नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय ने आज हुई सुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि जीएसटी संबंधी शिकायतों के निवारण में आ रही दिक्कतों के लिए जीएसटीएन के चेयरमैन और सीईओ जिम्मेदार होंगे।

याचिओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि अदालत द्वारा सितंबर व अक्टूबर महीने में दिए गए आदेशों और जीएसटीएन के अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं के साथ हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इस पर अदालत ने जीएसटीएन अधिकारियों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए जिसमें यह बताया कि कौन कौन सी जीएसटी संबंधी शिकायतों का कब और कैसे निवारण हुआ है?

शर्मा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर को आदेश दिया था कि केंद्रीय जीएसटी, दिल्ली जीएसटी और सीबीआइसी की बेवसाइट पर नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी की जानकारी डाली जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

इसी तरह 7 अक्टूबर को जीएसटीएन के साथ हुई बैठक में सिस्टम द्वारा जीरो क्रेडिट/डेबिट नोट स्वीकार नहीं करने पर चर्चा हुई। इस संबंध में सिस्टम में बदलाव पर जीएसटीएन ने जीएसटी नीति प्रकोष्ठ से विचार कर निर्णय लेने की बात कही। लेकिन इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अदालत में सुनवाई में भाग लेने वाले अधिवक्ता पुनीत अग्रवाल ने बताया कि अदालत के निर्देश पर जीएसटीएन अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं के बीच बैठकें हो चुकी हैं।

फिर भी जीएसटी संबंधी समस्याओं का पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ है। जीएसटी के दो साल भी जीएसटीएन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बीएस सूडोकू 3599

					4		7	
4	2	9		5	7			
		5		2	3			8
	9	6					8	3
2		4				1		9
1	5					7	4	
9			3	1		6		
			9	7		8	1	5
	6		4					

परिणाम संख्या 3598

6	3	9	2	8	1	5	7	4
4	5	1	9	7	6	2	8	3
8	2	7	5	4	3	1	6	9
7	1	4	6	9	5	3	2	8
9	6	2	4	3	8	7	5	1
5	8	3	1	2	7	9	4	6
1	9	6	7	5	4	8	3	2
2	7	8	3	6	9	4	1	5
3	4	5	8	1	2	6	9	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2135/2140, जौ 1825/1830, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4200/4225, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1530/1600,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2135/2140, गेहूं शरबती 2750/2850, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2950,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1423, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1510, फ्लैक 1450, डीएमओ 1010, टरपीन लैस बोल्ड 1525

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1000/1090, खुरपा 925/940, चाकू 900/1030, रसकट 800/820, शक्कर 1050/1080, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3400, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3380, शामली 3350,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 900/920, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4225, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2600/2700, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5700, गेहूं (मिल) 2180/2185, मक्की 2070/2075, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3900, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4490/4500,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3900/3950, जौ 2050/2075,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7600/7700, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1900/1920, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6000/6200,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8100, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7800/8400, उड़द धोया 9700/10700, छिलका 10400/12000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6200/6300, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3800/3900, शरबती स्टीम 4200/4300,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3925/3950, हरियाणा 3900/3930, राजस्थान 3850/3950, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2170/2175,

फाजिल्का
गेहूं 2160/2170, सरसों 4250/4300 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/3950,कपास देशी 4900/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5125, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2800,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2170/2180, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2160/2170, बिहार 2300/2325, दाल उड़द छिलका 9300/10500, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5300/5400, काबली चना 5100/6000, राजमां चित्रा पुणे 7500/9000, चीन 7500/8100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2175/2180, बासमती चावल 6400/6600, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2600/2700, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6300/6400,

हिसार
ग्वार 3900/3950, सरसों 4000/4100, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1100, मैदा 1175/1200, देशी घी (एक ली/जार) 375/465, रिफाइंड (टीन) 1290/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4000/4050, खल बिनौला मोटी 2100/2200, बिनौला 2500/3000, सरसों तेल 8550/8600, गेहूं 2125/2175, ग्वार 3850/3900, जौ 1825/1850, नरमा 5100/5150, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 243

बढ़ती आशंकाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का बुधवार को जोरदार बचाव किया लेकिन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। अब तक समस्या का कोई हल भी नजर नहीं आ रहा है। गत सोमवार को संसद में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर माह में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17 फीसदी की गिरावट आई। इसका अर्थ यह हुआ कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में कर संग्रह की वृद्धि दर 4.7 फीसदी से नीचे आ गई जबकि पूरे वर्ष के दौरान इसके 17 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कॉर्पोरेशन कर दर में कटौती ने इस संग्रह को किस हद तक प्रभावित किया है। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मोर्चे पर भी प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं है इसलिए केंद्र सरकार के राजस्व संग्रह में भारी कमी आ सकती है। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी। व्यय को कम करना या उसे टालना भी एक विकल्प है लेकिन इसका मध्यम अवधि में देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा।

इस बीच राज्यों की शिकायत है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने में देर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसकी बकाया राशि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यदि जीएसटी राजस्व की वृद्धि 14 फीसदी से कम रहती है तो केंद्र को राज्यों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसका केंद्र की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर होगा। जीएसटी के मोर्चे पर हर्जाने की गारंटी के बावजूद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब है क्योंकि मंदी ने उत्पाद और बिक्री कर संग्रह को भी प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकारों की उधारी चालू वर्ष में 20 फीसदी तक बढ़ सकती है। ऐसे में काफी संभावना है कि राज्यों का बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 फीसदी के बजट अनुमान से अधिक हो जाए। साथ ही राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता में हाल के वर्षों में गिरावट आई है क्योंकि राजस्व व्यय बढ़ा है। ऐसा आंशिक तौर पर कृषि ऋण माफी जैसी लोकलुभावन योजनाओं के कारण हुआ। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बताती है कि निकट भविष्य में इस रुझान में कोई बदलाव नहीं आने वाला। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले दबाव का असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है क्योंकि सरकार के पूंजीगत व्यय के दो तिहाई के लिए राज्य उत्तरदायी होते हैं। चालू वर्ष में राज्यों के पूंजीगत व्यय में भी काफी गिरावट आने की बात देखी गई है। इसका असर निकट भविष्य में मांग और संभावित वृद्धि दोनों पर होगा। इतना ही नहीं उच्च सरकारी ऋण भी कम ब्याज दरों के पारेषण को प्रभावित करेगा। बल्कि सरकारी घाटे में अहम वृद्धि मौद्रिक समायोजन की संभावनाओं को वैसे भी सीमित करती है।

चूंकि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के स्थायी रूप से उच्च वृद्धि दर के मार्ग पर लौटने की संभावना नहीं है इसलिए सरकार को राजकोषीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अगले कुछ सप्ताह में ऐसा किया जाना चाहिए और इसमें विशेषज्ञ समूह की सहायता ली जानी चाहिए। इससे न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति का सही आकलन होगा बल्कि नीति निर्माताओं को राजकोषीय खाका नये सिरे से खींचने का अवसर भी मिलेगा। सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तमाम लंबित मसलों को हल करना चाहिए ताकि कर संग्रह में सुधार हो सके। यह स्वीकार करना होगा कि व्यय को स्थगित रखने और जवाबदेहियों को सरकारी उपक्रमों पर टालने से समस्या हल नहीं होगी। इससे केवल भ्रम पैदा होगा और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा।

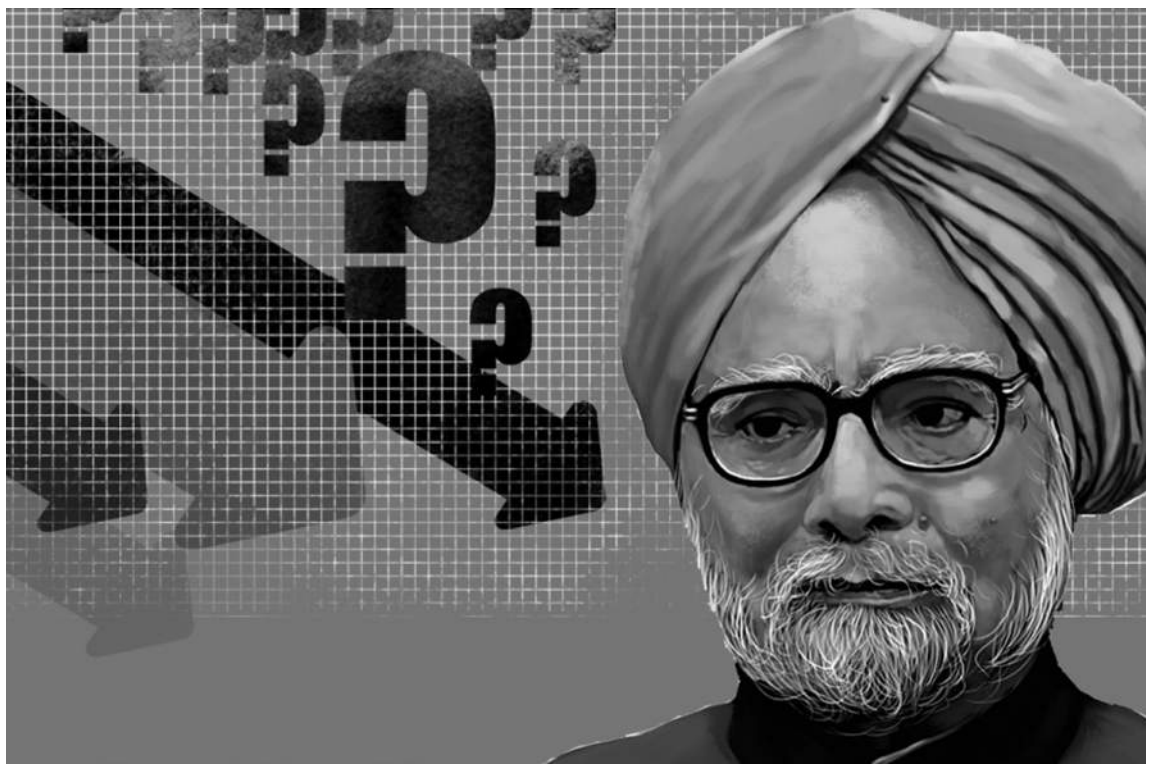

अजय मोहंती

डॉ. मनमोहन सिंह का बेसुरा गान

हम आज जो कीमत चुका रहे हैं उसमें पिछली सरकारों की गलत नीतियों की भी भूमिका है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **देवाशिष बसु**

वर्ष 2014 के आम चुनाव के पूर्व देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 'मौन' मोहन सिंह कहकर पुकारा था। डॉ. सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा जाता था कि वह देश में घट रही तमाम घटनाओं पर खामोशी का रुख अपनाए रहते हैं। इनमें भ्रष्टाचार के मामलों (राष्ट्रमंडल खेल, एयर इंडिया, दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयल और लोहा) से लेकर नीतिगत पंगुता और भूमि हथियाने के मामलों के साथ-साथ निर्भया जैसे मामलों से ठीक से न निपट पाना शामिल था। मोदी ने उस वक्त जनता के मिजाज को सही ढंग से समझा।

अब मोदी के चुप रहने की बारी है। डॉ. सिंह ने समाचार पत्र द हिंदू में आलेख लिखकर मोदी सरकार के आर्थिक प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि खलू कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर 15 फीसदी के निचले स्तर पर है, आम परिवारों की खपत चार दशक के निचले स्तर पर है, बेरोजगारी 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है, बैंकों का फंसा हुआ कर्ज अब तक के उच्चतम स्तर पर है, बिजली उत्पादन की वृद्धि 15 साल में सबसे धीमी है वगैरह...वगैरह। हालांकि मैं मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का आलोचक रहा हूं लेकिन देश की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर सिंह द्वारा दी जा रही वजहें और उनके द्वारा सुझाए जा रहे नीतिगत सुझाव पाखंड प्रतीत हो रहे हैं।

डॉ. सिंह कहते हैं कि सामाजिक मोर्चे पर आपसी विश्वास और आत्मविश्वास एकदम निचले स्तर पर है और इसका असर आर्थिक वृद्धि पर भी पड़ रहा है। फिलहाल सामाजिक भरोसे का हमारा तानाबाना पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उद्योगपति सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होने की आशंका में जी रहे हैं, बैंकर नए ऋण देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें आशंका है कि उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। उद्योगपति नई परियोजनाएं शुरू नहीं करना चाहते, तकनीकी क्षेत्र के स्टार्टअप निरंतर निगरानी और आशंका में जी रहे हैं जबकि नीति निर्माता सच बोलने या ईमानदार नीतिगत चर्चाओं से बच रहे हैं। डर और अविश्वास का असर आर्थिक लेनदेन पर पड़ता है और आगे चलकर यह मंदी का सबब बनता है।

चयनित पूर्वग्रह

यदि पिछली सरकारों से तुलना की जाए तो यह तस्वीर काफी अतिरंजित है। खासकर अगर सन 1991-96 की कांग्रेस सरकार से तुलना की जाए, जब सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। सन 2004 से 2014 तक के हालात भी इससे अलग नहीं थे। उस वक्त सिंह प्रधानमंत्री थे। सिंह की दलील में दो दिक्कतें हैं: वह चुनिंदा उठाते हैं और हालिया घटनाओं की बात करते हैं। पहला, भारतीय नागरिक और कारोबारी हमेशा से सरकार की दया पर रहे हैं। सरकार के पास उनको प्रताड़ित करने के सैकड़ों तरीके हैं। मोदी सरकार कुछ अलग नहीं कर रही है। सन 2010 में ही मैंने टैक्सटॉर्शन (करवसूली को हथियार बनाकर परेशान करना) जैसा शब्द गढ़ा था। सन 2013 में डॉ. सिंह के नेतृत्व में ही पुरातनपंथी कंपनी अधिनियम बना। कांग्रेस के कार्यकाल में कानूनों को पुरानी तिथि से लागू करने और जनरल ऐंटी अवॉयडेंस नियमों को याद कीजिए। वह भरोसे का कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं पेश करते।

आम जनता को भले ही पता नहीं हो लेकिन डॉ. सिंह को यह पता होगा कि आर्थिक कदमों के परिणाम थोड़ा विलंब से सामने आते हैं। स्पष्ट है कि आज जो हालात हैं उनका संबंध वर्षों पूर्व उठाए गए कदमों से होगा। हम आज जो कीमत चुका रहे हैं वह केवल मोदी सरकार की बदौलत नहीं है बल्कि उसमें पिछली सरकारों की गलत नीतियों की भी भूमिका है। मौजूदा आर्थिक मंदी का एक बड़ा कारण सरकारी बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्ट तरीके से दिए जाने वाले ऋण का बंद होना भी है। 10 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले किस प्रकार ऋण दिया जाता था।

व्यवस्था से नकदी के घटने के लिए मुझे इसके अलावा कोई बड़ी वजह समझ में नहीं आती। इस गलत आवंटन के चलते सरकार को आबादी के उत्पादक हिस्से से अधिकाधिक संसाधन जुटाने पड़े। इनमें निजी कारोबारी और परिवार शामिल हैं। इतना ही नहीं विकृत पूंजीवादियों और बैंकरों द्वारा की गई इन गड़बड़ियों के जवाबदेह मोदी नहीं बल्कि पिछली सरकारों के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आरबीआई के विभिन्न गवर्नर भी इससे बरी नहीं हैं। बल्कि मोदी ने तो डिफॉल्टरों पर लगाम लगाई है। कांग्रेस सरकार के अधीन उन्हें बैंकों से और पैसा मिला होता। मोदी के कार्यकाल में यह संभव नहीं।

नीतिगत उपचार

डॉ. सिंह को लगता है कि समाज की आर्थिक भागीदारी में विश्वास और भरोसा बहाल करके निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह झूठ है। अकेले भरोसे और विश्वास से आर्थिक वृद्धि नहीं हासिल होती। प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ बाजार में प्रवेश और निर्गम के सहज मार्ग से ऐसा होता है। मुझे याद नहीं आता कि सिंह सरकार ने ऐसा एक भी कदम उठाया हो जो इस व्यवस्था को आगे ले जाने वाला हो। यह भूलना आसान है कि सन 1990 में जब वह वित्त मंत्री थे तब भारत में प्रतिभूति घोटाला हुआ था और बिना नियमन के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से आम घरों को लूटा गया था। इसके अलावा भी तमाम वित्तीय घोटाले हुए थे। सरकारी बैंकों की भ्रष्ट ऋण व्यवस्था के तहत सरकारी धन की लूट हुई। दूरसंचार लाइसेंसिंग, एनरॉन और अन्य निजी बिजली परियोजनाओं में शासन की विफलता सामने आई। इन तमाम वजहों से मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच गई। जबकि नेतृत्व एक अर्थशास्त्री के हाथ में था।

इन तमाम तरह के कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई। वहां से उबरने में छह वर्ष लगे। फंसे हुए कर्ज से संबंधित एक नया कानून बनाना पड़ा लेकिन वह भी निष्प्रभावी साबित हुआ। वर्ष 2004-2014 की अवधि में बहुत व्यापक कुप्रबंधन देखने को मिला लेकिन वैश्विक संसाधन और चीन के कारण हो रहे नकदी लाभ की उपलब्धियों ने कमियों को ढक लिया। प्रतिस्पर्धा के बजाय विकृत पूंजीवाद पनपा, पारदर्शिता की जगह अस्पष्टता ने घेरे रखी। स्वच्छ और स्पष्ट नियमों के बजाय जटिल नियम बने। कुल मिलाकर व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। डॉ. सिंह द्वारा की गई आलोचना में कांग्रेस की कमियों को छिपाने की भावना अधिक है, बजाय कि नई व्यवस्था की कमियां उजागर करने के।

शीर्ष अदालत की जड़ता का सभी अदालतों पर असर पड़ता

अदालती आईना

एम जे एंटनी

हम सबने उन अप्रचलित कानूनों के बारे में सुना है जिन्हें सरकार समय-समय पर हटाती रहती है। ऐसे दो पुराने कानून तो विलक्षण हैं: विमान अधिनियम 1934 के मुताबिक पतंग उड़ाने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। इसी तरह भारत खजाना अधिनियम 1878 के मुताबिक मिट्टी के भीतर मौजूद कोई भी मूल्यवान वस्तु और 10 रुपये मूल्य वाली चीज को खजाना माना जाता है। सरकार की कोशिशों के बावजूद ऐसे कई पुराने कानून अब भी बदस्तूर लागू हैं। हालांकि कई नए कानूनों की तरह ये कानून अभी केवल कागजों में ही लागू हैं, लिहाजा वे तुलनात्मक रूप से नुकसानदायक नहीं हैं। इन कानूनों से जुड़े संवैधानिक सवालों पर उच्चतम न्यायालय से आखिरी राय का इंतजार है। पुराने दौर के इन मुकदमों में कई गंभीर मुद्दे हैं। इन कानूनों को विलंबित अवसान में रखना कानून के साथ खिलवाड़ करने जैसा है जिससे गलत आदेश आते हैं और नागरिक उसकी चपेट में आते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कुछ हफ्ते पहले अपने एक फैसले में ऐसा ही एक ज्वलंत खुलासा किया। भूमि अधिग्रहण मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ दायर अपीलों का निपटारा करते समय संविधान के अनुच्छेद 31(सी) की वैधानिकता काफी अहम रही। हालांकि न्यायालय ने यह फैसला नहीं किया है कि 1981 के मिनर्वा मिल्स वाद में निष्प्रभावी किए जाने के बाद भी क्या यह प्रावधान लागू है? यह सवाल 1996 से ही खड़ा हुआ था। एक पीठ ने इस मसले को पांच सदस्यों के संविधान पीठ को प्रेषित कर दिया। लेकिन यह मामला इसी तरह आगे बढ़ते हुए नौ न्यायाधीशों के पीठ तक जा पहुंचा। मुद्दा संपत्ति के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के परस्पर संबंध से जुड़ा है। वैसे ऐसे मामले बार-बार अदालतों में आते रहते हैं।

बहरहाल हम जिस भारत संघ बनाम तरसेम सिंह मामले का जिक्र कर रहे हैं, उसमें अनुच्छेद 31-सी को लागू करने पर जब विरोध किया गया तो न्यायालय के पास भी इसकी वैधानिकता परखने का कोई नियम नहीं था क्योंकि वर्षों से इस पर विचार ही नहीं हुआ था। न्यायाधीशों ने फैसले में लिखा, 'हम इस मामले के मद्देनजर यह मान लेंगे कि अनुच्छेद 31-सी मौलिक क्रियान्वयन की ही तरह अब भी लागू है और एक समुदाय के भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति को भी जोड़ा जाएगा।' कोई अनुमान ही लगा सकता है कि ऐसे कितने और मामलों में भी न्यायाधीशों ने धारणाओं के आधार पर ऐसे मुश्किल हालात में खुद को अलग किया है। लेकिन अदालत के अनिर्णय की वजह से अपने मुकदमे हारने वाले याचियों की हालत तो इससे भी बुरी है।

> सर्वोच्च अदालत तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण दौर में नजर आ रही है। बीते महीनों में नजर आए तमाम मुद्दे अब शांत हो चुके हैं। न्यायाधीशों की संख्या भी कम थी। अगले 17 महीनों के कार्यकाल वाले नए मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ को प्रेषित पुराने मामलों को अहमियत दे सकते हैं।

यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान के बारे में है। ऐसे मुकदमों की संख्या जानकर अचरज एवं सदमा लगेगा। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठों के समक्ष ऐसे 250 मामले अपने निपटान का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से कुछ मामले 1992 के बाद से ही अंतिम सुनवाई की बाट जोह रहे हैं। ऐसे 11 मामले सात न्यायाधीशों के पीठ के सुपुर्द किए जा चुके हैं। वहीं 130 से भी अधिक मामले ऐसे हैं जिनका निपटारा नौ न्यायाधीशों के पीठ को करना है। अगर एक संविधान पीठ नियमित तौर पर भी इन मामलों की सुनवाई करती है तो इनके निपटारे में कई साल लग जाएंगे।

इन मामलों के विषय राष्ट्रीय जीवन के हरेक पहलू, खासकर वित्त एवं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। सरकार अब एक श्रम संहिता तैयार कर रही है लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई 'उद्योग' की परिभाषा अब तक तय नहीं हो पाई है। यह अकल्पनीय है कि न्यायाधीशों के मन में उद्योग की संकल्पित अवधारणा के आधार पर न जाने कितने कामगारों ने मुकदमे जीते और हारे हैं। फिलहाल 520 श्रम विवाद अदालत के समक्ष लंबित हैं। इसी तरह प्रत्यक्ष कर के 3,000 से भी अधिक मामले और अप्रत्यक्ष कर के 520 मामले विचाराधीन हैं। उनमें से कई मामले उन कानूनों से भी जुड़े होंगे जो संविधान पीठों को भेजे जा चुके हैं लेकिन कभी उन पर बहस ही नहीं हुई। पहले के मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देते रहे हैं और उन्होंने आर्थिक मामलों को नजरअंदाज किया है। इससे ऐसी धारणा बनती गई है कि इस देश में कारोबार करने की राह में बड़ी बाधा न्यायपालिका भी है। उच्चतम न्यायालय की जड़ता नीचे की सभी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करती है।

सर्वोच्च अदालत तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण दौर में नजर आ रही है। बीते महीनों में नजर आए तमाम मुद्दे अब शांत हो चुके हैं। न्यायाधीशों की संख्या भी कम थी। अगले 17 महीनों के कार्यकाल वाले नए मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ को प्रेषित पुराने मामलों को अहमियत दे सकते हैं। अगर वह इस दिशा में पहल करते हैं तो आने वाले वर्षों के लिए एक प्रक्रियागत दृष्टांत साबित होगा।

कानाफूसी

प्याज की माला

देश के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर निकलने के बाद बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने प्याज की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। वैशाली जिले के विधायक शिव चंद्र राम ने नारे लगाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने स्टॉल लगाकर 35 रुपये किलो की दर पर प्याज बेचने का झूठा वादा किया था। उन्होंने कहा कि उनका विरोध इसलिए है ताकि नीतीश कुमार मजबूर होकर कुछ कदम उठाएं। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्याज की माला पहनकर राज्य सचिवालय के समक्ष विरोध किया था। प्याज के दाम बढ़ने पर उनकी शिकायत थी कि राज्य सरकार हालात को नियंत्रण में नहीं रख सकी। गौरतलब है कि बारिश के कारण मंडियों में प्याज की आवक कम होने से इसके दाम में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।

बेकाबू हालात

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हालात नियंत्रण में आते नहीं दिख रहे हैं। अब रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह निशाने पर हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक याचिका दाखिल करके कहा है कि सिंह को सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जाए। अदिति सिंह ने 2 अक्टूबर को पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था और उस विशेष सत्र में शामिल हुई थीं जिसका पार्टी ने बहिष्कार किया था। इसके पश्चात उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कांग्रेस विधायी दल की नेता आराधना सिंह के अनुसार अदिति सिंह ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे पहले गत रविवार को पार्टी ने अपने 10 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से पार्टी नेतृत्व का विरोध किया था और पार्टी की छवि धूमिल की थी।

अदिति सिंह

आपका पक्ष

बढ़ती जनसंख्या समस्याओं की वजह

देश की बढ़ती आबादी पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक प्रभावित कर रही है। पर्यावरण की अधिकांश समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हैं। आर्थिक, कृषि एवं औद्योगिक विकास जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है। औद्योगिक तथा तकनीक का विकास ही देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है लेकिन इनके विकास से भी पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। जनसंख्या की वृद्धि से जीवन स्तर गिर रहा है जिसके कारण आर्थिक स्तर भी गिर रहा है। भोजन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण अधिक हो रहा है अर्थात नगरों तथा कस्बों का विस्तार हो रहा है जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण अधिक हो रहा है। उच्च शिक्षा की सुविधाओं में भी कमी आ रही है क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस गति से शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है। राजनीति, धर्म, समाज तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी वास्तविक मूल्यों का पतन हो रहा है। इसलिए आज नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है। मनुष्य भी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रदूषित हो रहा है जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण में पर्यावरणीय क्षति की गंभीर समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है। अगर जनता का सहयोग प्राप्त हो तो स्थिति पर नियंत्रण पाना संभव है। देश-विदेश में किए गए अध्ययन यह बताते हैं कि लोग इस समस्या की व्यापकता से परिचित नहीं हैं। अत: सही दिशा में पहला कदम लोगों की आवश्यक जागरूकता पैदा करना है। इसके बाद लोगों के मूल्यों में परिवर्तन करके उनके व्यवहार को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।

देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार को नीतिगत उपाय करने चाहिए

हरिओम हंसराज, सारण

तकनीक के साथ बच्चों की पढ़ाई

तकनीक के इस दौर में छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई भी तकनीक के साथ हो रही है। लेकिन इसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आज अभिभावक बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं जिससे भविष्य में दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। स्मार्टफोन के बढ़ते प्रचलन से इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। छोटे बच्चे अगर लंबे समय तक मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहे तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है। अनेक छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग चुका है। यह शायद टीवी अधिक देखने या फिर मोबाइल के अधिक इस्तेमाल के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल फोन की तरंगों से भी नुकसान हो सकता है। मोबाइल फोन को सीने के पास रखने से मना किया जाता है क्योंकि इससे हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। आने वाले समय में 5जी तकनीक शुरू हो जाएगी जिसे कई मंचों पर खतरनाक बताया गया है। अत: बच्चों की पढ़ाई एक सीमा तक तकनीक के साथ ठीक है। अधिकता से कहीं बच्चों का भविष्य अंधेरे में न पड़ जाए।

विशाल कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

देश के कई शहरों में 100 रुपये से अधिक दाम पर बिक रहा प्याज

खराब प्रबंधन नीति भुगत रहे उपभोक्ता!

राजेश भयानी
मुंबई, 28 नवंबर

मुंबई समेत सभी प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में प्याज के खुदरा दाम प्रति किलोग्राम 100 रुपये पार जा चुके हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण आपूर्ति प्रबंध-आयात नीति और अत्यधिक फसल क्षति के कारण इतने अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। देश में कई थोक मंडियों में भी बढ़िया गुणवत्ता वाले प्याज के दाम इस सप्ताह की शुरुआत में 100 रुपये से अधिक बोले जा रहे थे, हालांकि अब इनमें कमी आने लगी है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई के खुदरा बाजार में प्याज के दाम प्रति किलोग्राम 120 रुपये, हैदराबाद में 100 रुपये, बेंगलूरु और इंदौर में 90 रुपये, अहमदाबाद में 85 रुपये और दिल्ली में 75 रुपये हैं।

शोधकर्ताओं और बाजार के भागीदारों के अनुसार निकट भविष्य में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दिसंबर के मध्य तक प्याज आपूर्ति में यह कमी बनी रहने की संभावना है तथा दाम कम होकर औसत स्तर तक आने में एक महीना लग जाएगा।

बागवानी निर्यातक संघ के अध्यक्ष अजीत शाह के अनुसार खरीफ फसल को पहुंचे नुकसान का असर अब भी दिख रहा है। अगले महीने के मध्य से लेकर महीने के अंत तक दामों में कमी आनी शुरू हो जाएगी।

चूंकि मॉनसून आने में देर हो गई थी और बाद में अत्यधिक तथा लंबे समय तक हुई बारिश ने प्याज की फसल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, इसलिए दामों में अचानक तेजी दिखाई दी और पिछले तीन महीनों से दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध और देश भर में व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाने के बाद नवंबर से दामों में कमी आने की संभावना दिख रही थी, लेकिन फसल को पहुंची क्षति इस क्षेत्र द्वारा लगाए गए अनुमान की तुलना में बहुत गंभीर थी। इसी वजह से आपूर्ति अब भी उतनी अच्छी नहीं है, जितनी इस समय तक होनी चाहिए थी।

अजीत शाह ने कहा कि सरकार ने आयात नियमों में ढील दी है, लेकिन इससे आयातकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और यह अधूरी साबित हुई है तथा आयातित प्याज की आपूर्ति सीमित रही है। अगर आयात नियमों में ज्यादा ढील दी जाती, तो आपूर्ति बढ़ने से दाम काबू में लाने में मदद मिल जाती।

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने 30 नवंबर, 2019 तक प्याज आयात के लिए फ्यूमिगेशन (धूम्रीकरण) की शर्त में ढील दी थी। आयातक सीमा शुल्क विभाग की शीघ्र मंजूरी और दुबई जैसे व्यापारिक केंद्रों से आयात करने के लिए और ज्यादा राहत चाहते थे।

अब तक व्यापारी मिस्र और तुर्की आदि से आयात का अनुबंध कर चुके हैं लेकिन इनकी मात्रा ज्यादा नहीं हैं क्योंकि भारतीय बंदरगाहों पर खेप पहुंचने में 20 दिन लगते हैं और सभी व्यापारी यह जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। दुबई से एक या दो दिन में खेप आती है। अफगानिस्तान से वाघा सीमा के जरिये प्याज आना शुरू हो चुका है।

हालांकि पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के संगमनेर और सोलापुर में, गुजरात के गोंडल और महुआ में, राजस्थान के अलवर में और दिल्ली की आजादपुर मंडी में आवक हो रही है तथा अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के दाम कम होकर 65 रुपये से 75 रुपये तक हो चुके हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार कई मंडियों में औसत दाम गिरकर तकरीबन 50 रुपये से 55 रुपये प्रति किलोग्राम तक तथा कुछ जगहों में इससे भी नीचे आ चुके हैं।

प्याज के खुदरा दाम

शहर	20 नवं	27 नवं	अंतर
अहमदाबाद	70	85	21.4
बेंगलूरु	70	90	28.6
दिल्ली	65	75	15.4
हैदराबाद	60	100	66.7
मुंबई	80	120	50.0

मूल्य रुपये प्रति किलो, अंतर प्रतिशत में, स्रोत- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, संकलन- बीएस रिसर्च

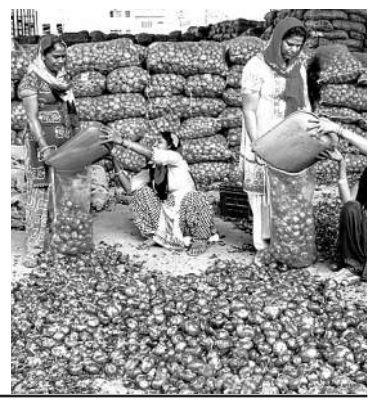

तकनीक से कम नुकसान

राजेश भयानी
मुंबई, 28 नवंबर

महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों - पुणे, अहमदाबाद और नाशिक में किसानों के खेतों पर अनियमित मॉनसून का असर जांचने के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारी बारिश ने खरीफ के अंत में खड़ी फसल और रबी की पौध को प्रभावित किया है। पुणे स्थित आईसीएआर-प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओजीआर) द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार बारामती और पुरांदर में खरीफ फसल के संबंध में नुकसान की तीव्रता 80 प्रतिशत तक रही है। वहां फसल अब भी जलभराव वाली स्थिति में थी क्योंकि किसानों ने बुआई की समतल भूमि वाली पद्धति अपनाई थी। इससे जल निकासी व्यवस्था बिगड़ गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में खरीफ के अंत वाली फसल को भारी संक्रमण के रोग सहने पड़े जिससे 60 प्रतिशत तक फसल क्षति हुई। भारी बारिश की वजह से रबी प्याज की पौध पर भी असर पड़ा था जिससे रबी फसल के रकबे में काफी कमी आई। डीओजीआर के निदेशक डॉ. मेजर सिंह के अनुसार जिन किसानों ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया, उन्हें कम नुकसान हुआ।

स्वर्ण कारोबार के लिए आईबीजेए शुरू कर रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

राजेश भयानी
मुंबई, 28 नवंबर

आभूषण उद्योग के इतिहास में पहली बार उद्योग से जुड़ा एक संगठन सराफा व्यापारियों और जौहरियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर रहा है। उद्योग सराफा कारोबार के लिए हाजिर एक्सचेंज के पक्ष में रहा है, लेकिन इस बारे में सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। अब इंडियन बुलियन ऐंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) ने अपना बिजनेस टु बिजनेस (बी2बी) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का निर्णय लिया है जो शुरुआत में सराफा कारोबारियों और जौहरियों की ओर से की जाने वाली मांग और आपूर्ति के लिए स्पष्ट दामों के साथ कारोबारियों और जौहरियों को परस्पर जोड़ेगा। इसके बाद इसकी योजना बिजनेस टु कंज्युमर (बी2सी) प्लेटफॉर्म शुरू करने की है जहां उपभोक्ता स्पष्ट कीमतों के साथ अपनी पसंद के विनिर्माताओं से आभूषण खरीद सकेंगे।

आईबीजेए के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, 'हम कल 29 नवंबर को बी2बी साइट शुरू कर रहे हैं। बाद में, शायद कुछेक तिमाहियों के उपरांत, हम बी2सी की भी शुरुआत करेंगे। हम जौहरियों को उनके आभूषणों की बिक्री के लिए कम लागत वाला प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं।'

- आज से शुरू हो रही है बिजनेस टु बिजनेस वेबसाइट
- बाद में बिजनेस टु कंज्यूमर सेवा की भी होगी शुरुआत
- जौहरियों और सराफा कारोबारियों को मिलेगी अपनी मांग-आपूर्ति के सौदे करने में मदद
- स्वर्ण आयात में कमी लाने में भी मिलेगी सहायता
- जौहरियों या सराफा कारोबारियों के पास पड़े सोने की सीधी आपूर्ति हो सकेगी अन्य कारोबारियों को

इस प्रयास से ऑनलाइन राष्ट्रीय हाजिर एक्सचेंज का माहौल और मंच तैयार होने की उम्मीद है जिसकी नई व्यापक स्वर्ण नीति के अंतर्गत परिकल्पना की गई है। मेहता ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य किसी एक राज्य के आभूषण डिजाइन का विस्तार विभिन्न राज्यों में करना है।

इससे जौहरियों को एक-दूसरे से जुड़ने में मदद मिलेगी और आभूषण की प्रचार लागत में भी कमी आएगी। अन्यथ यह कार्य किसी महंगी प्रदर्शनी के जरिये करना पड़ता है।

इससे सोने के आयात में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी क्योंकि जौहरियों या सराफा कारोबारियों के पास पड़े सोने की आपूर्ति सीधे अन्य कारोबारियों को की जा सकती है। वर्तमान में सराफा की जरूरत केवल आयात के जरिये ही पूरी की जाती है जहां आपसी संपर्क नहीं होता है।

जुलाई में स्वर्ण आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने के बाद अवैध आयात और इसके परिणामस्वरूप काला बाजारी में काफी इजाफा हुआ है। कारोबारी अवैध रूप से आयातित सोने का इस्तेमाल पुराने गहनों के रूप में कर रहे हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऐसी गतिविधियां रुकने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Nov 28	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,770.5	2.7	1,885.5	-4.0
Copper	5,925.5	4.8	6,159.2	0.0
Nickel	14,445.0	-9.9	15,153.6	-5.4
Lead	1,946.0	-6.6	2,122.9	3.6
Tin	16,375.0	3.4	17,178.8	1.9
Zinc	2,335.0	3.3	2,667.6	4.1
Gold ($/ounce)	1,455.1*	-5.5	1,641.2	-2.4
Silver ($/ounce)	16.9*	-7.7	19.3	-5.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.5*	5.8	63.6	7.0
Natural Gas ($/mmBtu)	2.5*	11.1	2.5	10.9
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	185.2	14.9	299.9	3.9
Maize	182.1*	0.1	302.4	-0.1
Sugar	342.6*	10.8	490.5	2.3
Palm oil	655.0	20.7	1,024.0	17.1
Rubber	1,553.4*	5.5	1,815.6	-6.9
Coffee Robusta	1,384.0*	4.2	1,878.5	-13.9
Cotton	1,431.0	11.2	1,564.2	-9.3

* As on Nov 28, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.6& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	20.5	13134
Oil and Oilseeds	286.0	75914
Spices	0.3	14
Metal(Nov 27)		
Metal- non ferrous	3742.3	56985
Metal- precious	9291.2	570
and gas(Nov 27)		
Gas	2994.4	41786
Oil	13163.5	2012

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	223.6	106591
Grains	263.2	104710
Oil and Oilseeds	734.7	468655
Others	191.4	70130
Pulses	108.7	65330
Spices	64.7	31677

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Nickel (Nov 29)	1077.1	2.0
Aluminium (Nov 29)	132.1	1.4
Aluminium Mini (Nov 29)	131.6	0.3
Cotton (Nov 29)	19040.0	0.3
Cardamom (Dec 13)	2852.9	0.1
Gold Petal (Nov 29)	3882.0	0.1
Losers (* % Change)		
Mentha Oil (Nov 29)	1253.2	-1.5
Zinc Mini (Nov 29)	185.2	-1.3
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4125.0	-0.9
Silver Mini (Nov 29)	44049.0	-0.9
Silver Micro (Nov 29)	44047.0	-0.9
Silver (Dec 05)	44040.0	-0.9

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	809.8	0.9
Soyabean Indore (Dec 20)	4060.0	0.8
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7531.0	0.3
Coriander-Kota (Dec 20)	6675.0	0.2
Guar Seed 10 (Dec 20)	4141.5	0.2
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4307.0	0.1
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	1948.5	-3.8
Barley Jaipur (Apr 20)	1701.0	-1.3
Chana-Bikaner (Dec 20)	4371.0	-0.8
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4164.0	-0.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1072.0	-0.5
Jeera Unjha (Dec 20)	16260.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	5.2
Gold Petal-Mumbai (Nov 29)	3882.0	2.4
Cotton-Rajkot (Nov 29)	19040.0	1.9
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Nov 29)	1253.2	-10.0
Copper Mum (Nov 29)	431.0	-3.0
Alumini-Mumbai (Nov 29)	131.6	-3.0
Aluminium Mum (Nov 29)	132.1	-2.7
Zinc Mini Mumbai (Nov 29)	185.2	-2.1
Lead Min Mumbai (Nov 29)	152.4	-1.8
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	2852.9	-1.2
Lead Mum (Nov 29)	154.1	-0.7
Zinc Mumbai (Nov 29)	187.9	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3362.0	3.4
Soy Bean Indore (Dec 20)	4060.0	1.1
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18640.0	0.5
Moong-Merta City (Dec 20)	6583.0	0.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2128.5	0.3
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5628.0	-5.4
Coriander-Kota (Dec 20)	6675.0	-5.0
Jeera Unjha (Dec 20)	16260.0	-1.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7531.0	-0.8
Crude Palm Oil Kandl (Nov 29)	674.1	-0.5
Maize-Sangli (Dec 20)	1863.0	-0.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	95.....(95)
Aluminium ingots /kg	135.....(135)
Brass sheet cutting /kg	311.....(312)
Brass utensil scraps/kg	290.....(291)
Copper heavy scrap /kg	408.....(407)
Copper utensil scraps/kg	380.....(380)
Copper wire bar /kg	441.....(440)
Lead ingots /kg	152.....(152)
Nickel Cathodes /kg	1085.....(1085)
Tin slabs /kg	1230.....(1225)
Zinc slabs /kg	191.....(191)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10686.....(10686)
DCH - 32 /Qtl	11445.....(11445)
Jaydhar /Qtl	10208.....(10208)
Shankar- 6 /Qtl	11304.....(11304)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	885.....(890)
Castor Comm /10kg	875.....(880)
Ricebran oil/10kg	760.....(760)
Groundnut oil /10kg	1020.....(1020)
Linseed oil /10kg	845.....(845)
Karanji /10kg	780.....(780)
Palm oil /10kg	742.....(742)
Sunflower exp ref /10kg	830.....(830)
Sunflower oil exp /10kg	785.....(790)
Soyabean ref / 10kg	795.....(790)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3452-3572 .....(3382-3552)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	57.72.....(58.11)
Brent Crude (UK)	63.35 .....(63.66)
Brent Crude (WTI)	58.11.....(58.11)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.5.....(2.5)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	248.17 .....(253.59)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37781.....(37754)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	37933.....(37906)
Silver.999/ kg	44345.....(44425)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18570.85	18548.95
Alumini-Mumbai (M)	1 K	137.80	135.65
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1885.00	1900.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2120.90	2123.05
Brass-Jamnagar (M)	1 K	297.65	300.15
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2967.00	3000.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4238.45	4211.55
Castor Seed-Kadi (N)	X	4200.00	4200.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4294.50	4297.70
Chana Delhi (N)	1 Q	4468.20	4447.50
Chana-Akola (N)	X	4450.00	4406.25
Coriander-Gondal (N)	X	6700.00	6700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	7042.20	6950.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7108.95	7026.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2100.00	2020.85
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2036.65	1955.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	18477.20	18501.15
CPO-Kandla (M)	10 K	666.20	666.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	673.90	677.60
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	874.55	880.95
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1534.65	1537.90
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3462.80	3466.40
Gold Ahm (M)	10 G	37751.00	37771.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30322.00	30338.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3790.00	3791.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7565.00	7593.75
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4075.20	4061.25
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4050.00	4100.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1014.40	1021.50
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.30	93.15
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17100.00	17100.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16540.00	16525.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1009.85	1001.90
Kapas-Rajkot (N)	X	996.20	992.70
Lead Mum (M)	1 K	155.55	155.20
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1900.00	1920.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2156.65	2167.50
Maize-Erode (N)	X	1908.00	1914.30
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2100.00	2107.50
Maize-Sangli (N)	X	1856.45	1871.65
Moong-Merta City (N)	1 Q	6543.75	6555.55
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4488.50	4462.75
Nickel Mumbai (M)	1 K	1075.00	1082.50
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3350.00	3250.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3248.00	3285.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	351.80	352.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34783.35	35000.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	790.00	781.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2081.95	2078.50
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	737.90	733.15
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	799.55	801.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	797.05	796.95
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	804.50	800.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13000.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13042.00	13075.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44319.00	44253.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4012.00	4014.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3975.00	4007.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3974.65	3984.75
Soy Bean-Akola (N)	X	4020.00	4000.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33013.00	33000.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	797.50	798.20
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27810.00	27900.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28700.00	28940.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25930.00	25870.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3345.00	3350.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3416.55	3414.15
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3296.25	3296.25
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3502.40	3504.75
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3346.65	3329.15
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3130.40	3131.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5940.90	5950.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2270.00	2265.85
Wheat Kota (N)	1 Q	2139.20	2128.25
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2195.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2082.50	2070.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2215.00	2210.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4605.90	4625.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	189.20	189.15

* as on Nov 27, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Nov 29	19090, 19090, 18990, 19040	319	56	791
Dec 31	19220, 19290, 19200, 19220	1378	239	9515
Jan 31	19430, 19430, 19420, 19420	17	4	2164
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2010, 2015, 1945.5, 1948.5	55800	3075	43160
Jan 20	2020, 2023, 1961, 1970.5	39690	2813	38420
Feb 20	2031, 2031, 1980, 1986	6620	512	18900
Mar 20	2058, 2058, 2001, 2015	1020	87	2220
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1079, 1079, 1072, 1073	212	46	596
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1078, 1079, 1070.5, 1072	926	414	3891
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1718.5, 1718.5, 1701, 1701	20	2	270
May 20	1710, 1710, 1710, 1710	210	3	210
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4139, 4160, 4105, 4141.5	39740	2424	62540
Jan 20	4173, 4197.5, 4145, 4182	23500	1283	38780
Feb 20	4210, 4220, 4210, 4220	80	8	610
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4170, 4184, 4140, 4164	5055	332	41175
Jan 20	4212, 4230, 4190, 4210	4620	319	18845
Feb 20	4160, 4164, 4160, 4164	30	6	3480
Mar 20	4104, 4112, 4082, 4100	70	13	2465
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Nov 29	670, 670, 664.3, 668	15570	842	13570
Dec 31	672, 674, 664.6, 673	22590	1511	51880
Jan 31	671.7, 673.5, 663, 671.6	1560	113	10060
Mentha Oil MCX(1 K)				
Nov 29	1275, 1275, 1252.5, 1253.2	22.68	30	90.72
Dec 31	1273.9, 1275.5, 1262.5, 1264.6	138.96	324	293.04
Feb 20	4070, 4109, 4062, 4101	15040	1251	71000
Mar 20	4102, 4138, 4100, 4128	4770	454	17790
Apr 20	4164, 4164, 4164, 4164	10	1	130
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7535, 7589, 7466, 7531	13435	1224	30290
Jan 20	7645, 7700, 7580, 7637	11740	1093	39625
Feb 20	7751, 7760, 7751, 7760	15	3	165
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4411, 4430, 4359, 4371	14450	1059	36400
Jan 20	4407, 4426, 4361, 4373	10080	735	27210
Mar 20	4350, 4350, 4315, 4315	140	6	1380
Apr 20	4325, 4325, 4310, 4310	70	5	190
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2848.9, 2880.1, 2848, 2852.9	0.7	7	4.3
Jan 15	2849, 2849, 2828, 2835.5	0.4	4	7.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6670, 6697, 6476, 6675	4310	371	8830
Jan 20	6660, 6680, 6492, 6657	2270	178	4130
Apr 20	6980, 7050, 6870, 6940	360	32	2310
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16260, 16330, 16230, 16260	543	169	3123
Jan 20	16105, 16105, 15980, 16030	195	57	990
Mar 20	15660, 15660, 15660, 15660	3	1	219
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5604, 5658, 5600, 5628	775	140	9335
Mar 20	6012, 6040, 5980, 6010	345	65	1540
Apr 20	6196, 6196, 6014, 6050	55	11	1195
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Nov 29	132.5, 132.5, 131.85, 132.2	55	4	580
Dec 31	132.85, 133.55, 132.85, 133.2	3690	532	9265
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Nov 29	131.85, 132.45, 131.75, 132	16	11	305
Dec 31	132.7, 133.55, 132.65, 133.2	1394	1142	3558
Jan 31	134.7, 134.7, 134.2, 134.35	8	8	105
Copper MCX(1 K)				
Nov 29	430.4, 430.4, 428.95, 429.35	42.5	17	695
Dec 31	434.55, 435.4, 433.6, 434.5	9437.5	3064	14622.5
Jan 31	439.7, 440.3, 438.75, 439.05	70	28	592.5
Lead MCX(1 K)				
Nov 29	151.8, 154.7, 151.8, 153.25	10	2	135
Dec 31	153.5, 154.1, 153.4, 153.75	9470	1465	7955
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.6, 154.1, 153.5, 153.8	2798	2206	2752
Jan 31	153.9, 154.25, 153.85, 153.95	7	7	35
Nickel MCX(1 K)				
Nov 29	1060.7, 1089, 1040.1, 1045.7	10.25	39	2.5
Dec 31	1048.1, 1052.9, 1028, 1035.5	9384	5597	2710.5
Jan 31	1046.5, 1048, 1025, 1031.1	78	51	40.5
Zinc MCX(1 K)				
Nov 29	189.15, 189.2, 187.75, 188.7	15	3	535
Dec 31	185.8, 186.3, 185.55, 185.85	15225	2552	16745
Zinc Mini MCX(1 K)				
Nov 29	186.3, 188.5, 186.3, 187.1	3	3	27
Dec 31	185.9, 186.3, 185.55, 185.9	4856	3786	5328
Jan 31	185.05, 186.25, 185.05, 185.95	47	41	301
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	37573, 37725, 37540, 37685	4.21	3653	5.13
Feb 05	37586, 37791

इतिहास और प्रौद्योगिकी का नजारा प्रस्तुत करता...

कोलकाता का नया रिजर्व बैंक संग्रहालय

नम्रता आचार्य

क्या आप उसी हैंड आयरन प्रेस- प्रिंटिंग मशीन से अपना नाम छपवाना चाहते हैं जिससे 20वीं शताब्दी के पहले दशक में सरकारी बॉन्ड छपा करते थे? भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कोलकाता में खुले अपने नए संग्रहालय में आपको यह मौका दे रहा है। अंग्रेजों के जमाने में बनी 112 साल पुरानी यह मशीन 2016 तक इस्तेमाल में थी। मशीन का कामकाज संभालने वालों का कहना है कि यह अब भी अच्छी हालत में है और कई साल काम कर सकती है। इसलिए जब 2016 में बॉन्ड छापने के लिए मैन्युअल प्रिंटिंग की जगह कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तो इसे धूल चाटने के लिए गोदाम में रखने के बजाय संग्रहालय में रखने का विचार आया।

मार्च 2019 में जब आरबीआई ने देश में अपना दूसरा संग्रहालय कोलकाता में खोला। दस साल पहले इसकी परिकल्पना की गई थी और इसे उसी इमारत में खोला गया है जहां भारत में इसका पहला दफ्तर था। आरबीआई का सबसे बड़ा संग्रहालय मुंबई में है। लेकिन इसके उलट कोलकाता संग्रहालय में बहुत ज्यादा कलाकृतियां नहीं हैं। इसके बजाय इसमें देश के मौद्रिक इतिहास को दिखाने के लिए ऑगमेंटेड रिएलिटी और इंटरेक्टिव सिमुलेशन जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। संग्रहालय के कर्मचारियों का कहना है कि इसी वजह से इस संग्रहालय को विकसित करने में दस साल लग गए। आरबीआई ने हाल में संग्रहालय में हेरिटेज वॉक की शुरुआत की जहां वरिष्ठ कर्मचारी लोगों को आरबीआई की समृद्ध विरासत से रूबरू कराते हैं। संग्रहालय की इमारत 8 काउंसिल हाउस कोलकाता के दशकों पुराने वाणिज्यिक केंद्र बीबीडी बाग के बीचोबीच स्थित है। बीबीडी बाग का खुद अपना समृद्ध इतिहास रहा है। इसी इमारत में 1935 में आरबीआई के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। तब आरबीआई ने एलायंस बैंक ऑफ शिमला से यह इमारत पट्टे पर ली थी। बाद में एलायंस बैंक ऑफ शिमला बिक गया और आरबीआई ने इसे परिसमापकों से ले लिया। यह इमारत मशहूर बांग्ला इंजीनियर और उद्योगपति सर राजन मुखर्जी की फर्म ने बनाई थी। उन्हें विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज बनाने का श्रेय भी जाता है।

परिकल्पना में आने के करीब 10 वर्ष बाद कोलकाता में खुला आरबीआई संग्रहालय

कुछ साल पहले तक 8 काउंसिल हाउस में सोने की एक तिजोरी थी और कटे-फटे नोटों की काटछांट होती थी। आज यह प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का प्रतीक है। उदाहरण के लिए संग्रहालय के बीचोबीच एक मूर्ति रखी गई है जो करेंसी नोटों के चलन में कमी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के उभार को दिखाती है।

आरबीआई के इतिहास को पैनलों में दिखाया गया है जो घूमने वाली टेबल को चलाने पर रोशन होते हैं। इसकी शुरुआत 1934 में आरबीआई के शुरू होने के साथ होती है और समापर 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के साथ। इस दौरान 12 जनवरी, 1946 की नोटबंदी के इतिहास को देखा जा सकता है जब आजादी से पहले की सरकार ने 1,000 और 10,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसमें एक आभासी पुस्तिका में आप हवा में हाथ से पन्ने पलटकर भारत में बैंकिंग के इतिहास को देख सकते हैं। एक गेमिंग स्टेशन में आप धन के समय और वेग को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर आभासी नियंत्रण कर सकते हैं।

सोने की मूल तिजोरी में दिखाया गया है कि इस बहुमूल्य धातु को कैसे संभालकर रखा जाता है। आप यह आभास कर सकते हैं कि सोने की 12.5 किलो की सिल्ली को उठाना कैसा लगता है। संग्रहालय में आप खुद को सोने की सिल्लियों में तौल सकते हैं।

संग्रहालय में देश के मौद्रिक इतिहास को दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। जैसे पाई को चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई और सरकार के बीच कविता के रूप में हुए संदेशों का आदानप्रदान। पाई को 1942 में चलन से बाहर किया गया था। एक रुपये में 192 पाई होते थे। मुद्रास्फीति के दबाव और ढलाई की ऊंची लागत के कारण इसे बंद करना पड़ा। लेकिन दस साल बाद मिंट मास्टर ने इसे फिर शुरू करे का प्रस्ताव दिया। 1952 में तत्कालीन वित्त सचिव के जी अंबेगांवकर ने कविता के रूप में पाई का मृत्युलेख लिखा था। इसे संग्रहालय में दिखाया गया है। उन्होंने कविता के अंत में लिखा था कि क्या मंत्री इसमें अंतिम शब्द कहेंगे? तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने भी इसका जवाब कविता के रूप में दिया था।

कोलकाता के आरबीआई संग्रहालय में कम ही कलाकृतियां हैं लेकिन यह सही मायनों में आपको भारत के मौद्रिक इतिहास की उतारचढ़ाव भरी यात्रा पर ले जाता है।

व्हाट्सऐप की सुरक्षा प्रणाली का हो ऑडिट

नेहा अलावधी

केंद्र ने व्हाट्सऐप जासूसी मामले में इजराइली फर्म को भी भेजा नोटिस

भारत ने व्हाट्सऐप का दुरुपयोग करके भारतीय नागरिकों की जासूसी करने का आरोप झेल रही इजराइली फर्म को नोटिस जारी किया है और भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सर्ट-इन) ने व्हाट्सऐप सुरक्षा एवं प्रणालियों का ऑडिट करने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।

विपक्ष ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि क्या सरकार ने कोई स्पाईवेयर खरीदा है? प्रसाद ने इसका सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि सरकार की एक मानक परिचालन प्रकिया (एसओपी) होती है और सरकार उसी के तहत काम करती है। उन्होंने कहा, 'हमने एनएसओ को भी नोटिस भेजा है।' प्रसाद ने कहा कि भारतीय मीडिया में व्हाट्सऐप के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा के साथ छेड़छाड़ के लिए स्पाइवेयर पेगासस के प्रयोग संबंधी खबरें आई थीं।

वह कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा स्पाइवेयर के सहारे कुछ भारतीयों को निशाना बनाने के सवाल का जबाव दे रहे थे। सर्ट-इन कंप्यूटर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है और साइबर सुरक्षा में सेंध लगने वाले मामलों के लिए उसे सूचित किया जाता है। सर्ट-इन ने व्हाट्सऐप से 9 नवंबर को सूचना मांगी थी, जिसमें व्हाट्सऐप सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं का ऑडिट एवं निरीक्षण करना शामिल है। प्रसाद ने बताया कि व्हाट्सऐप ने 18 नवंबर को जवाब दिया और 26 नवंबर को उनसे अतिरिक्त विवरण मांगा गया।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि व्हाट्सऐप पर कुछ लोगों के संदेशों और बातचीत की निगरानी करवाए जाने के मुद्दे पर कहा कि इस मामले में आज तक उनके मंत्रालय के पास कोई शिकायत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ लोगों के नाम आए, किंतु इनमें से किसी ने भी अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं करवाई? प्रसाद ने कहा कि यदि प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए तो सरकार सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप ने अभी तक उन्हें 121 लोगों के नाम की सूची नहीं दी है।

उन्होंने कहा कि क्या यह एक संयोग है कि जिन लोगों के नाम आए हैं, उनमें से अधिकतर (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी के प्रति स्थाई विचार रखते हैं। प्रसाद ने कहा, 'भारत अपनी डेटा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत आज दुनिया में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रहा है। बाहर से आने वाली कंपनियों का यहां स्वागत है, किंतु हमारी जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।'

उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या के मामलों में हिंसा को प्रोत्साहित करने के मकसद से सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले संदेशों के बारे में सरकार ने व्हाट्सऐप से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि पाया गया कि जिस क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं हुईं, वहां बहुत सारे मैसेज भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार की बात को मानते हुए व्हाट्सऐप ने अब महज पांच संदेशों का नियम तय कर दिया है। इसी के साथ भारत में उन्होंने अपना शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि यदि हिंसा से जुड़ी कोई घटना होगी तो व्हाट्सऐप पर आने वाले किसी भी संदेश के मूल स्थल की पहचान बतानी होगी। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में पता चला है कि ऐसे बहुत से संदेश की शुरुआत पड़ोसी देशों से होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, 'भारत की जनता की निजता और डिजिटल सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी डिजिटल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे।..यदि पड़ोसी देश, आतंकवादी या भ्रष्टाचारी लोग देश को डिजिटल आधार पर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।' प्रसाद ने कहा कि सरकार डेटा संप्रभुता के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और अमेरिका सहित किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह सरकार डेटा संरक्षण विधेयक तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक मजबूत विधेयक होगा और इसे लेकर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। *(साथ में एजेंसियां)*

पृष्ट 1 का शेष

महाराष्ट्र में आघाडी सरकार

पाटील को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है जबकि कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। गठबंधन के सुचारू संचालन के लिए सीएमपी में दो समन्वय समितियों के गठन की बात कही गई है। एक समिति राज्य मंत्रिपरिषद के भीतर समन्वय का काम देखेगी जबकि दूसरी समिति सहयोगी दलों के बीच समन्वय बनाए रखने का काम करेगी। एमवीए के एजेंडा में राज्य भर में एक रुपये शुल्क वाले क्लिनिक स्थापित करने की भी बात कही गई है। इन क्लिनिक में मरीजों के सभी पैथोलॉजिकल परीक्षण किए जा सकेंगे।

सीएमपी में शिवसेना के उस चुनावी वादे को भी जगह मिली है जिसमें 10 रुपये में भरपेट खाना देने की बात कही गई थी।सीएमपी ने राज्य सरकार में खाली पड़े सभी पदों को भरने का भी वादा किया है। झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत योग्य लोगों को 500 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्र वाला आवास बिल्कुल मुफ्त देने की भी बात कही गई है जबकि अभी उन्हें 300 वर्गफुट का आवास ही दिया जाता है। खेतिहर मजदूरों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण देने का भी किया है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के निर्माण, फसल बीमा योजना की समीक्षा एलं सूखा प्रभावित इलाकों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने का भी जिक्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किया गया है।

तमिलनाडु में बनेगा नया रॉकेट लॉन्च पैड

टी ई नरसिम्हन

- भविष्य में उन्नत तकनीक वाले रॉकेट प्रक्षेपित करेगा लॉन्च पैड
- भारत से प्रक्षेपित होने वाले उपग्रहों की संख्या लगातार बढ़ रही
- फिलहाल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हैं दो लॉन्च पैड

केंद्र सरकार तमिलनाडु में एक नया रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित करने की योजना बना रही है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दो लॉन्च पैड हैं। भारत से घरेलू और विदेशी उपग्रहों के लॉन्च की बढ़ती संख्या को देखते हुए नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास (डोनेर), एमओएस पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 'सरकार ने तमिलनाडु राज्य में कुलसेकरपत्तनम के पास रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।' हालांकि मंत्री ने इसके उपयोग के बारे में विस्तार से नहीं बताया और अभी इसरो अधिकारियों से बात नहीं की जा सकी लेकिन नए लॉन्च पैड का उपयोग भारत के भविष्य के रॉकेट जैसे यूनिफाइड मॉड्यूलर लॉन्च व्हीकल (यूएमएलवी), जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (जीएसएलवी मार्क-3) और अवतार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल (अवतार आरएलवी) के साथ साथ छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा पीएसएलवी रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा।

इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों की संख्या इस वर्ष 30 पार कर गई है। वर्ष 2018 में अंतरिक्ष एजेंसी ने 17 मिशन लॉन्च किए थे। वर्तमान में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा का एसएचएआर स्पेसपोर्ट लांचरों के एकीकरण का कार्य करता है। इसमें दो ऑपरेशनल लॉन्च पैड हैं, जहां से सभी जीएसएलवी और पीएसएलवी उड़ानें होती हैं। इसरो ने वर्कहोर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के साथ अपने अधिकांश उपग्रह लॉन्च किए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 1994 से 2015 तक पीएसएलवी ने 84 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिनमें से 51 अंतरराष्ट्रीय उपग्रह थे। इसरो स्वदेशी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन एवं स्टेज के साथ जीएसएलवी के अगले संस्करण जीएसएलवी मार्क-3 विकसित कर रहा है जो 4 टन वाले उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अंतरिक्ष एजेंसी छोटे रॉकेटों को ले जाने के लिए छोटे रॉकेटों पर भी काम कर रही है। स्वदेशी रूप से विकसित स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) को वैज्ञानिकों द्वारा छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 2,000 किमी से कम दूरी वाले लो-अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।

राजपक्षे की वापसी से तमिलनाडु के नेता चिंतित

राज्य के राजनीतिक दलों में श्रीलंका में तमिलों के भविष्य को लेकर बढ़ा भय, उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र से मदद की लगाई गुहार

टी ई नरसिम्हन

श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति और पूर्व रक्षा सचिव गोटाभाया राजपक्षे के तमिलनाडु के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों जे जयललिता और एम करुणानिधि के साथ तकरारपूर्ण संबंध रहे थे। 2009 में श्रीलंका में अशांति के अंतिम चरण के दिनों में तमिलों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं के सिलसिले में ये दोनों नेता गोटाभाया से नाराज थे।

गोटाभाया के अपने भाई महिंदा के साथ फिर से सत्ता में आ जाने से तमिलनाडु में राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। महिंदा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा प्रधानमंत्री हैं।

अब राज्य के राजनीतिक दलों में श्रीलंका के तमिलों के भविष्य को लेकर डर बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने केंद्र से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने का आग्रह किया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राज्य के सभी राजनीतिक दल एकमत नजर आ रहे हैं। वे युद्ध अपराधों और 2009 से तमिलों के मानवाधिकार हनन के मसले पर महिंदा के खिलाफ जांच की मांग करते रहे हैं। 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) की हार के साथ ही श्रीलंका में गृहयुद्ध का अंत हो गया था।

तीन दशक लंबे गृहयुद्ध का अंत करने के लिए ज्यादातर सिंहलियों ने गोटाभाया को युद्ध का नायक करार दिया। इस युद्ध में करीब 1,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों की संख्या में लोग गायब हुए। लेकिन मुस्लिम सहित अल्पसंख्यक आबादी में भय बना हुआ है और सत्ता में उनकी वापसी से अल्पसंख्यक समुदाय खुश नहीं हैं। एक खबर आई थी उत्तर पश्चिम श्रीलंका में मतदान केंद्रों पर मुस्लिमों को ले जारी बसों पर कुछ अनजान बंदूकधारियों ने फायरिंग की थी, हालांकि इसमें किसी के मारे जाने की सूचना नहीं थी। गोटाभाया ने सिंहल बहुल जिलों में एकतरफा जीत हासिल की है जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सजीत परमदासा को ज्यादातर वोट तमिल बहुल वाले देश के उत्तर और पूर्वी इलाके तथा मुस्लिम समुदाय से मिले। इनमें चाय बागान में काम करने वाले भारतीय मूल के कामगार भी शामिल हैं।

> पूर्व मुख्यमंत्रियों जयललिता और करुणानिधि के साथ तकरारपूर्ण संबंध रहे थे राजपक्षे के

रिर्पोर्टों के अनुसार सिंहली राष्ट्रवाद के इस नए चरण में एक मजबूत सरकार का नेतृत्व मजबूत नेता के हाथों में है जिसका चुनाव सिंहल बौद्ध आबादी ने किया है। श्रीलंका की आबादी में सिंहल समुदाय की हिस्सेदारी 70 फीसदी है। वहीं यहां 12.6 फीसदी तमिल हिंदू, 10 फीसदी मुस्लिम और 8 फीसदी ईसाई आबादी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 की अपनी श्रीलंका की यात्रा में यह आवश्वासन दिया था कि भारत श्रीलंका में तमिलों और अन्य समूहों की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा और देश के दूरदराज इलाकों में 10,000 अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए भारत के सहयोग की पेशकश की थी। इन मकानों में 4,000 मकान तैयार भी किए जा चुके हैं। श्रीलंका के राजपक्षे परिवार पर चीन का प्रभाव अधिक है।

वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता और राज्य के मत्स्यपालन मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि भारत सरकार श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करेगी। उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और राज्य की सत्तारूढ़ दल द्रमुक ने भी इसी तरह की बात कही है। द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने मोदी से श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'राजपक्षे पूरी तरह से तमिलों के खिलाफ रहे थे और उनकी कार्रवाई के जो नतीजे आए उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया।'

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एमडीएमके के महासचिव वाइको ने कहा कि राजपक्षे की जीत तमिलों के लिए एक बुरा दिवस था। वाइको ने रविवार को रिर्पोटरों से कहा, 'उनके शासन में रहने के दौरान हजारों की संख्या में तमिलों की हत्या की गई, महिलाओं का यौन शोषण किया गया और बच्चों व बूढ़ों का बर्बरतापूर्ण कत्ल किया गया।'

पीएमके संस्थापक एस रामदास ने कहा कि अब श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एकमात्र उपाय एक अलग तमिल ईलम की स्थापना है। उन्होंने कहा कि तमिलों को श्रीलंका में पहले जो दोयम दर्ज का नागरिक माना जाता था अब चौथे दर्ज का भी नहीं माना जाएगा। राजनीतिक समीक्षक एस रवींद्रन दुरईसामी ने कहा कि यदि मतदान के रुझान पर नजर डालें तो श्रीलंका में आए चुनाव परिणाम का प्रभाव सीमन की अगुआई वाली नाम तमिलर काची (एनटीके) तक ही सीमित है। एनटीके जिसका मतलब हम तमिल पार्टी हैं होता है एक क्षेत्रीय पार्टी है। कहा जाता है कि इस पर लिट्टे और उसके नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन का प्रभाव है। एक कट्टर विचारधारा के साथ इस पार्टी की नींव 1958 में पड़ी थी जिसे 2009 में तमिलनाडु में सीमन ने पुनर्जीवित किया।

उन्होंने कहा, 'इसका प्रभाव 2009 और 2011 में करुणानिधि के खिलाफ रहा। जयललिता के निधन के बाद जो लोग श्रीलंका के मुद्दों को लेकर गंभीर थे वे सीमन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एनटीके को मिले 5.58 फीसदी वोट के पीछे श्रीलंका का मुद्दा ही था। लेकिन प्रभाव के संदर्भ में देखें तो यह मामूली असर ही डालेगा।' तमिलनाडु के राजनीतिक दलों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षे ने तमिलनाडु के राजनेताओं से मौकापरस्त राजनीति से दूर रहने का आग्रह किया है। नमाल महिंदा राजपक्षे के पुत्र हैं।

गुरुवार को दिल्ली में राजपक्षे की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन करते एमडीएमके नेता और कार्यकर्ता *पीटीआई*

भारत पहुंचे श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति

श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटभाया राजपक्षे सत्ता की बागडोर संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत गुरुवार को भारत पहुंचे। वह शुक्रवार को दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह भारत ने कहा था कि वह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के साथ काम करने की दिशा में आशान्वित है और उम्मीद जताई कि यह सरकार (राजपक्षे सरकार) देश में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। दूसरी ओर एमडीएमके के नेता वाइको और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे के खिलाफ गुरुवार सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 125 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। *भाषा*